corrections in the Delimitation Commission's Order No. 41 dated the 24th May, 1975 in respect of the State of Punjab, under sub-section (2) of section 11 of the Delimitation Act, 1972. [*Placed in Library. See No.* LT-10822/76].

(2) A copy of the Report (Hindi version) on the General Elections held during the year 1974 to the Legislative Assemblies of Manipur, Nagaland, Orissa, Uttar Pradesh and Pondicherry —Statistical. [*Placed in Library. See No.* LT-10823/76].

ANNUAL REPORT & ACCOUNTS OF ONGC FOR 1974-75 & REVIEW ON THE REPORT

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Annual Report together with the Audited Accounts (Hindi and English versions) of the Oil and Natural Gas Commission for the year 1974-75 and of its subsidiary company Hydrocarbons India Private Limited, New Delhi, for the year 1974, under sub-section (4) of section 23 read with sub-section (4) of section 22 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the above Report. [*Placed in Library. See* No. LT-10824/76].

RAILWAYS (WARE-HOUSING AND WHARFAGE) THIRD AMDT. RULES, 1976

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the Railways (Warehousing and Wharfage) Third Amendment Rules, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 1504 in Gazette of India dated the 24th April, 1976, issued under section 47 of the Indian Railways Act, 1890. [*Placed in Library. See* No. LT-10825/76].

12.00 hrs.

DEMANDS* FOR GRANTS, 1976-77— *Contd.*

MINISTRY OF STEEL AND MINES—*Contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Steel and Mines. Out of 4 hours allotted, 1 hour 20 minutes have been taken. The balance is 2 hours 40 minutes. I shall call the Minister at 2 O'clock so that he may finish in 40 minutes.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD): I also want to intervene.

MR. SPEAKER: You can do so earlier. I shall call the minister at 2 o'clock. Shri Jagannath Mishra

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मंत्री महोदय की कितनी बड़ी क्षमता है, उनका विभाग भी उतना ही बड़ा है और इस विभाग के संचालन में उन्होंने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

हमारे देश में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की संख्या 129 है और उसमें कुल पूंजी 7,000 करोड़ रुपये की है। इसमें से अकेले इस्पात के प्रतिष्ठान में हमारी 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी लगी हुई है, यानी हम अपनी पूंजी का लगभग 30 परसेंट उसमें लगाते हैं।

इससे पूर्व कभी भी इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं हुई। यह सिद्धान्त की बात है कि जो इकनामिक विभाग है, उस पर इस सदन में चर्चा हो, सदस्यों के मन्तव्यों को सुना जाये और साथ ही जो सुधार की गुंजाइश हो वह भी की जाये। इस बार जैसा हो रहा है, गत दो तीन बरसों में ऐसा नहीं हुआ है, इसलिये मैं मंत्री महोदय को फिर धन्यवाद देना चाहता

*Moved with the recommendation of the President.

हूं कि उन्होंने हमें इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है।

इसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे के द्वारा जो सराहनीय काम हो रहे हैं, उसको भी भुला नहीं सकते हैं। इसके पहले जब भी लोहे की चर्चा होती थी, तो यह कहा जाता था कि सामान पहुंचाने में वैगनों की कमी के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है, लोहे के लाने, ले जाने के लिये जितनी वैगन्ज चाहिये रेलवे मिनिस्ट्री के पास उन वैगनों की कमी नहीं है। इस प्रकार से यह काम ठीक चल रहा है।

इस बार उत्पादन भी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब मैं यह ढूंढता हूं कि इससे पहले इतना उत्पादन क्यों नहीं होता था, तो बहुत से कारण नजर आते हैं और उनमें सबसे ज्यादा प्रबल हम एमरजैन्सी को पाते हैं। एमरजैन्सी के चलते प्रतिष्ठानों में वातावरण बिल्कुल शांत है, कर्मचारी काम में लगे हुए हैं और उत्पादन अपनी गति से चल रहा है। यह प्रसशंसनीय है और संतोष का विषय है।

इस्पात उद्योग से हम लोगों को फायदा क्या होता है? जहां सन् 1973–74 में हमें इससे घाटा हुआ है वहां सन् 1974–75 में 37 करोड़ रुपये का नफा अवश्य हुआ है। लेकिन बोकारो में हमें घाटा हुआ है।

फिर भी हमारा नैट प्राफिट 36.59 करोड़ था। हमने सरकार से कर्जा भी लिया है और कर्ज लेकर इस प्रतिष्ठान को चला रहे हैं। कर्ज की राशि 345 करोड़ के बराबर है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस लोन की राशि का हमें क्या इन्टरेस्ट देना पड़ता है। जितने और प्रतिष्ठानों में इन्टरेस्ट देना पड़ता है, यदि उसके हिसाब से देखते हैं तो हमारा नफा अब तक 12 करोड़ के घाटे में जाकर पड़ जाता है।

मंत्री महोदय ने एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना बनाने की व्यवस्था की है। इस्पात उद्योग के लिये ये एक 25 वर्षीय योजना बनाने का विचार करते हैं, शायद यह योजना बन भी चुकी है। लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। मैं आशा करता हू कि जल्दी ही सरकार के पास यह रिपोर्ट आ जायेगी और सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। लेकिन इसका जो विकास होगा, यह तो 25 वर्ष के आर्थिक अस्तित्व पर निर्भर करता है। जैसा आर्थिक विकास होगा, वैसी ही उत्पादन की गति भी रहेगी। इसलिये हमें समय की ओर भी देखना होगा।

हमारे देश में 5 7 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन हो रहा है। हम जो पहले सामान इम्पोर्ट करते थे, उसमें भी ह्रास हुआ है और अब हम लोहे से बनी हुई वस्तुओं को काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करने लगे हैं, यह इस मंत्रालय का बड़ा सुलक्षण है।

स्टील अथारिटी के द्वारा पिग आयरन का एक्सपोर्ट अप्रैल, 1975 से फरवरी, 1976 तक जो हुआ है वह 9,166 रुपये का हुआ है। वर्ष 1974–75 की तुलना में इस वर्ष इस्पात के उत्पादन में 8 लाख टन की वृद्धि हुई है, यानी वर्ष 1975–76 में 57 लाख टन का उत्पादन हुआ। बोकारों को छोड़ कर अन्य संयंत्रों में 82 प्रतिशत क्षमता का हमने उपयोग किया है।

सलेम प्रोजेक्ट के लिये 517 करोड़ रुपये की जरूरत है। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि अगर उसे 116 करोड़ रुपये भी मिल जायें तो 30 हजार से लेकर 35 हजार टन कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील शीट के उत्पादन के लिये एक कोल्ड रोलिंग मिल की स्थापना करने में

सुविधा हो सकती है। दूसरे प्रोजेक्ट विशाखापत्तनम और विजयनगर की योजनाएं चालू करने के लिये स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने तैयारी की है, जो कि सरकार के विचारार्थ शीघ्र ही पेश कर दी जायेगी।

पांचवीं योजना की समाप्ति पर हमारा इस्पात का उत्पादन 9.86 मिलियन टन हो जाता है और हमारी खपत जो होगी वह 7.658 मिलियन टन होगी। इस तरह से हम खर्च के बाद अपने उत्पादन में कुछ बचाव कर सकेंगे जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और उससे फारेन एक्सचेंज से जो रुपया मिलेगा उसको हम विकास के काम में लगा सकेंगे।

आयरन और बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसको सुधारने के लिये ऐसा निर्णय लिया गया है कि उस पर सैस लगाया जाये।

मैं यहा एक बात बताना चाहता हूं कि भारत दुनिया के कुछ और भागों में भी इस्पात का कारखाना खोलने जा रहा है। यह अबूधाबी में इस्पात का कारखाना खोलेगा। इसके बदले में अगले वर्ष अबूधाबी से भारत को 8 लाख टन तेल मिलेगा।

मैं बोकारो के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। देश के औद्योगिक सर्वांगीण विकास के लिये इस्पात का बहुत बड़ा महत्व है। वहां पर 1 मई, को प्रधान मंत्री ने गर्म पट्टी का उद्घाटन किया है। इसकी कल्पना का श्रीगणेश पूज्य श्री नेहरू जी के द्वारा हुआ था। इसका काम तीन चरणों में पूरा होगा। गर्म पट्टी के निर्माण में 941 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। इससे सन् 1979 तक 1 करोड़ 75 लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य संभव हो सकेगा। यह कारखाना भारत और रूस की मैत्री आधार पर बन रहा है और यह दोनों देशों की मैत्री और सद्भावना का प्रतीक है। यह बहुत सन्तोष का विषय है।

बोकारो इस्पात कारखाना अपनी उस हाट स्ट्रिप, गर्म पट्टी, मिल की बदौलत, जिस का 1 मई को प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, द्वारा उद्घाटन किया गया, इस वर्ष 5,70,000 टन बिक्री योग्य इस्पात तैयार कर सकेगा। यहां जो प्लेटें और चादरें तैयार होंगी, वे ट्यूब, तेल की खोज, उर्वरक और रक्षा सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण, जहाज और रेल के डिब्बों के निर्माण, तथा इन के साथ ही मोटरगाड़ी, रेफ्रीजेरेटर, कोल्ड स्टोरेज आदि अनेक उपभोक्ता उद्योगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी।

शीघ्र ही इस इस्पात कारखाने के इर्द-गिर्द 300 सहायक उद्योगों की स्थापना हो जायेगी, जिस से रोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध हो जायेंगे।

भिलाई इस्पात संयंत्र को उत्तरी कोरिया से 12,000 टन रेल-पटरियों की पूर्ति करने का आर्डर मिला है। यह बड़ी सराहनीय बात है। इसी प्रकार मिश्र से 22,000 टन फिश-प्लेटों का आर्डर मिला है। इस से पूर्व इस संयंत्र ने दक्षिणी कोरिया को 15,000 टन फ़िश-प्लेटें भेजी हैं।

यह बड़े संतोष की बात है कि इन इस्पात कारखानों में वर्कर्ज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमैंट की समुचित व्यवस्था की गई है और उन को मकान, पानी, बिजली, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवहन आदि की सहूलियतें प्रदान की गई हैं।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पश्चिमी देशों की तरह यहां भी वर्कर्ज के लिए हालिडे होम्ज की स्थापना की जाये। मंत्रालय की रिपोर्ट में इस का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि गैर-सरकारी इस्पात प्रतिष्ठानों को नैशनलाइज कर दिया जाये।

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

मन्त्री महोदय से मेरा सब से महत्वपूर्ण और अन्तिम सुझाव यह है कि इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि हम लोग मजदूरों को हेय दृष्टि से न देखें। पाश्चात्य देशों की किताबें पढ़ने से मुझे पता चला कि वहां चाहे कोई जज या मैजिस्ट्रेट हो, कोई मन्त्री हो, या कोई मोटर का ड्राइवर हो, सब बराबर होते हैं और उन में कोई भेदभाव नहीं होता है। मन्त्री महोदय इस विचार-धारा के प्रबल समर्थक हैं। इसलिए मैं उन से आग्रह करूंगा कि वह एक ऐसा वातावरण बनायें जिस में वर्कर्ज को हेय दृष्टि से न देखा जाये और उन को समाज में उचित स्थान दिया जाये, ताकि उन का यह अनुभव हो कि यह देश उन का है और इस के विकास में वे भी भागीदार हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री दामोदर पांडेय (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, मेरे सभी पूर्ववक्ताओं ने मंत्री महोदय और इस मन्त्रालय की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यह उचित ही है कि इस मन्त्रालय ने पिछले वर्षों में जिस तरह से काम किया है, उस की तारीफ की जाये। इस में कोई दो मत नहीं हो सकते हैं कि इस मन्त्रालय के द्वारा काफी अच्छा काम हुआ है। लोहे इस्पात और अन्य मेटल्ज का उत्पादन काफी बढ़ा है। यह कोई अत्युक्ति नहीं है कि जितना हम उम्मीद करते थे, उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ा है। अगर यह कहा जाये कि मन्त्री महोदय के सफल नेतृत्व और अच्छे निर्देशन के कारण इतना उत्पादन बढ़ा है, तो वह भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

यह ठीक है कि अब तक बहुत काम हुआ है, लेकिन हम मन्त्री महोदय से कुछ अधिक की अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि वह ऐसा दिशा-निर्देश दें, ऐसे ठोस कदम उठायें, जिस से इस विभाग की अन्य खामियों को भी दूर किया जा सके। मैं चन्द बातें आप के सामने रखना चाहता हूं।

हमारे देश में आयरन ओर का विशाल भंडार है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कोयला खदानों में पहले जो स्थिति थी, उसी तरह आयरन ओर के सम्बन्ध में कुछ काम तो नैशनल मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा किया जाता है, कुछ स्टील प्लांट्स की अपनी कैप्टिव माइन्ज हैं और कुछ प्राइवेट सैक्टर की माइन्ज हैं। इसी तरह कुछ एक्स-पोर्ट पब्लिक सैक्टर के द्वारा होता है और कुछ एक्सपोर्ट प्राइवेट सैक्टर के द्वारा होता है। यह स्थिति बड़ी दयनीय है। आयरन ओर का उत्पादन जिस ढंग से होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है, बल्कि उस का उपयोग गलत ढंग से होता है, और एक्सपोर्ट के मामले में भी इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से उस का उपयोग किया जाता है।

अगर हम यह मान कर चलते हैं कि आयरन ओर का हमारा भंडार कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी गलतफहमी है और हम को उस का शिकार नहीं होना चाहिए। आज प्राईवेट सैक्टर के मालिकों द्वारा 50 परसेंट से कम के ओर कन्टेन्ट के आयरन ओर को खेतों में फ़ेंक दिया जाता है और केवल 50 परसेंट से 70 परसेंट तक के ओर कन्टेन्ट के आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। अमरीका में आज भी ओपन ग्राउंड जा कर बहुत डिफीकल्ट कन्डीशन्ज में 35 परसेंट ओर कन्टेन्ट का आयरन ओर माइन किया जाता है, यह देख कर हम समझ सकते हैं कि किस तरह हम अपनी सम्पत्ति की बर्बादी कर रहे हैं। इस लिए मेरा सुझाव है कि यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि हमारा आयरन ओर का भंडार कभी खत्म नहीं होने वाला है।

इस के अतिरिक्त हम को आयरन ओर खदानों से जल्दी एक मैनेजमेंट के अधीन लाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। हो सकता है कि गोआ में डिफ्रेंट कन्डीशन्ज होने के कारण वहां पुराने रीति-रिवाजों के अनुसार काम हो रहा हो। लेकिन आज के संदर्भ में इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वहां अलग तौर-तरीके और अलग ढंग से काम हो। बिहार और उड़ीसा के बैल्ट में आयरन ओर माइन्ज प्राईवेट सैक्टर में जिस तरह काम करती हैं, अगर उस को लूट कहा जाये, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भी वहां मजदूर को दो या तीन रुपये मजदूरी दी जाती है। यह स्थिति असहय है। इस लिए जल्दी से जल्दी इस का निराकरण किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय इस मामले में सक्षम हैं। इस लिए आशा है कि वह इस दिशा में कठोर कदम उठायगे।

कई अन्य मिनरल्ज के बारे में भी हम लोग बहुत गलतफहमी में हैं। एक ऐसा जमाना था, जब हम लोग यह समझते थे कि हमारे देश में इतना मैंगानीज ओर पैदा होता कि हम दुनोया की मार्केट्स पर कब्जा कर लेंगे। जो भी काली वस्तु पाई गई, उस को हम मैंगानीज के नाम पर एक्सपोर्ट करने लगे। नतीजा यह हुआ कि हम ने सारे संसार की मार्केट को खो दिया।

मैंगानीज की स्थिति भी आयरन ओर की सी है। कुछ माइन्ज प्राईवेट सैक्टर में हैं और कुछ पब्लिक सैक्टर में हैं। कुछ में मजदूरों को दो रुपए मजदूरी मिलती है और कुछ में पांच रुपये मिलती है, कुछ मजदूरों को राशन मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम को यह सोचना चाहिए कि हमारे देश में मैंगानीज का कोई अक्षय भंडार नहीं है, वह भी खत्म होने वाली चीज है।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण करने के बाद ही खदानें अच्छी हालत में चल सकती हैं, और कोयला खदानों के सम्बन्ध में हम ने यह कर के दिखा दिया है हम ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम खदानों का संचालन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो फिर कोई वजह नहीं है कि मैंगानीज, लाइमस्टोन, मैग्नीसाइट और काईनाइट आदि प्रैशस मिनरल्ज की खानों का राष्ट्रीयकरण न किया जाये। हम यह बात केवल मजदूरों के कल्याण की दृष्टि में नहीं कर रहे हैं—हालांकि यह बात भी ठीक है कि हम उन लोगों के कल्याण की भावना मन में रखते हैं, इस लिए कि जब हम दिन-रात उन के बीच में रहते हैं, तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन के कल्याण की बात करें—बल्कि इस से देश का भी कल्याण होगा।

आज इस्पात उद्योग को जिस तरह से लूटा जा रहा है इन प्राइवेट मालिकों के द्वारा उस को भी हम बहुत हद तक चेक कर सकेंगे, रोक सकेंगे और आज चूंकि हम अधिक से अधिक इस्पात पब्लिक सैक्टर में पैदा कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि यह सब जो कैप्टिव माइन्ज की तरह से होना चाहिए था, पब्लिक सैक्टर के हाथों में होना चाहिए था, आज इन को प्राईवेट हाथों में छोड़ दिया गया है।

तीसरा विषय कापर का है। आप जानते हैं अभी भी कापर हम इम्पोर्ट करते हैं। यह बात सही है कि उस दिशा में काफी सुधार हुआ है। हम लोगों ने काफी कापर का प्रोडक्शन किया है। पिछले वर्ष और उस के पहले के वर्षों की अपेक्षा तो उस में काफी सुधार हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति कितने दिन तक चलेगी इस के बारे में सोचना पड़ेगा। एक तरफ़ तो मलाजखंड में अपार भंडार का कापर पड़ा हुआ है जिस की निकासी का अभी तक कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ। खेतरी में इतना बड़ा स्मेल्टर बना दिया और वहां कोई ओर नहीं है जिस से हम मेटर बना सकें। घाटशिला का स्मेल्टर

[श्री दामोदर पांडे]

जो पुराने जमाने में बना था उस की भी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का पूरा उपभोग नहीं हो रहा है। जो मेटल हम इम्पोर्ट करते हैं उस को हम अपने देश में बढ़िया तरह से पैदा कर सकते हैं। स्मेल्टर कैपेसिटी है। कोई वजह नहीं है कि दो दो स्मेल्टर जो बड़े बड़े अपने देश में हैं उन का सही उपयोग न हो। मेरा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी सिर्फ उन स्मेल्टरों का उपयोग करने के लिए नहीं बल्कि देश की अर्थ नीति को सुधारने के लिए, इम्पोर्ट नहीं हो, इस के लिए जो भी ओर कन्टेंट नहीं जहां भी अवेलेबल हो उस की निकासी का प्रबन्ध किया जाय चाहे वह मलाजखंड में हो या घाटशिला का एक्सटेंशन हो, उसके आस पास की जितनी खदाने हैं उन से ओर निकालने का सवाल हो इन सब के लिए प्रबन्ध किया जाय। जो पुराने इंडियन कापर कारपोरेशन के मालिक थे वे अच्छी से अच्छी किस्म का ओर निकाल कर चले गए, अब उसका राष्ट्रीयकरण हो गया है तो अब बड़े व्यापक पैमाने पर उन इलाके का सर्वेक्षण करा सकते हैं। वहीं इतना और पैदा हो सकता है जिस का घाटशिला में उपयोग कर सकते हैं।

एक और सवाल था। हमारे धनबाद जिले में टूंडू एक जगह है जहां इनका लेड स्मेल्टर है। वह काफी छोटा है। अपने देश में लड की काफी डिमांड है और उस का उत्पादन भी बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा रहे हैं। अब लेड स्मेल्टर हम अलग से लेड और जिंक मिलाकर विशाखापट्टम में बैठाने जा रहे हैं। अगर विशाखापतनम में नया कारखाना हम खोल सकते हैं तो क्या कारण है कि टूंडू के स्मेल्टर का विस्तरा नहीं हो सकता। उस से थोड़ी बहुत चांदी निकल सकती है। तो चांदी तो हम मिट में दे ही देते हैं, चांदी तो बिहार रख नहीं लेता है। अगर उस कारखाने का विस्तार किया जाता तो हम समझते हैं कि वह ज्यादा उपयोगी होता और सुविधापूर्ण होता। अब विशाखापट्टम में आप काफी आगे बढ़ गए हैं, हमें कोई एतराज नहीं है आप वहां भी कारखाना खोलें लेकिन जो लेड स्मेल्टर की आवश्यकता है और जो अपने देश में इस मेटल की आवश्यकता हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि आप टूंडू का जो कारखाना है उस का भी विस्तार करें और जो भी आस पास मलाजखंड में थोड़ा लेड और मिले उसको वहां भी सप्लाई किया जाय और वहां उससे लेड निकालने की व्यवस्था की जाय।

वर्क्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की जो बात है यह ठीक है कि इस्पात उद्योग में और खदानों में, मेटल उद्योग में उन्होंने बखूबी ढंग से इस को चलाया है और इसको चलाने के क्रम में बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन एक ऐसा काम होने जा रहा है कि जिस से बड़ा नुक्सान होगा और जो मजदूर संघ में काम करने वाले लोग हैं वे इस को खतरनाक पहलू मानते हैं। मैं इसके बारे में अलग से मंत्री महोदय से बात नहीं कर सका, उस के लिए मुझे मौका नहीं मिला लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो खेतरी में चुनाव के द्वारा वर्क्स पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं इस से वर्क्स पार्टिसिपशन किस तरह का मिलेगा यह बात समझ में नहीं आती है। आज तक पूरे देश में जितना भी वर्क्स पार्टिसिपेशन होने जा रहा है वह ट्रेड यूनियन्स के साथ समझौता कर के, आपस में सहयोग और आपस में एक दूसरे को ऐडजस्ट कर के हर जगह उस के लिए कमेटी बनाई है और वह सफल भी सिद्ध हुई है। लेकिन यह चुनाव का वातावरण पैदा करने की बात आप वर्क्स पार्टिसिपेशन में करेंगे तो उस की वही दुर्दशा हो जायगी जो वर्क्स कमेटी की हुई। चुनाव की पद्धति अपना कर आप उद्योग धन्धों में शांति नहीं ला सकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि यूनियनों से बात कर के समझौते के रास्ते से उस को करना चाहिए

था। चुनाव पद्धति से यह बात सही ढंग से नहीं हो सकती।

श्री धनशाह प्रधान (शहडोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस्पात और खान मंत्रालय के नियंत्राणाधीन अनुदानों की मांगों की चर्चा के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इस में मजदूरों की दशा पर भी गौर किया गया है। सही माने में मजदूर ही राष्ट्र का निर्माता है। हमारी आय इस के ही परिश्रम और अपने पन की भावना पर टिकी हुई है।

मेरा निवेदन है कि कोयला और खान के क्षेत्र में आदिवासी जनता को अधिक स्थान दिया जाय। ये लोग सरल होने के नाते राष्ट्र की सेवा में अधिक कार्य अपनी सहज ईमानदारी से करते हैं। आपातकाल की स्थिति में माननीया प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम के लागू होने से इन के शोषण के सारे कार्य रुक गए। यह उन के और राष्ट्र के लिए एक शुभ लक्षण है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक कल्याणकारी कार्य है। बेकार आदिवासी युवकों की सेवा इस दिशा में लेने पर उदारता पूर्वक विचार किया जाये। उन की इस राष्ट्र सेवा जैसी भावना का उपयोग देश के लिए किया गया है। इन के शोषण को रोकने के विषय में सरकार ने विचार किया है और ये क्रियाशील भी रहे हैं। फिर भी कोई ऐसी नीति सरकार निर्धारित करे जिससे कोयला खदानों और उस के मजदूरों की स्थिति अच्छी बने। मंत्री महोदय ने इस दिशा में जो कुछ किया है उस के लिए मैं उन को धन्यवाद देता हूं।

देश के विभिन्न खदानों की दशा पुराने मालिकों ने खराब कर के रख दी है जिस के परिणामस्वरुप अभी कुछ घटनाएं हुई। इस के लिए मैं निवेदन करूंगा कि देश की समस्त खदानो की पुन: एक बार जांच कर लें ताकि ऐसी स्थिति न आए जिस में मजदूरों का नुकसान हो क्योंकि मजदूरों का जीवन अमूल्य है। उस की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

कोयला खदानों में क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति का निर्माण किया जाय ताकि वहां की जनता की भर्ती और उस क्षेत्र की समृद्धि हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRI D. D. DESAI (Kaira): While supporting the Demands for Grants, I would like to make a few observations and suggestions to prompt the Ministry and the officials to some action.

We have the tradition of manufacturing steel. Probably it goes to the historical pillar which is in Delhi itself. We have been the supplier of steel for Damascus sword. If we had been the steel-maker for the world once, then what is it that had prevented us from making steel which would be superior to any other steel which is manufactured in any part of the world? Have we done that or are we still going to do it? Are we utilising our even installed capacity? We have talked about annual targets or annual capacities. Is it related to rated capacities of our machinery? My own feeling is that we have completely ignored these features in spite of our being in steel-making business for nearly 2000 years and even in modern times for over 60 years period.

We have today the raw material—iron ore—to an extent which, according to the United Nations, can be comparable probably to that of no other country in the world. But those who do not possess iron ore have far exceeded our production and when we were already manufacturing steel, they were not in the picture and on the steel-manufacturing map of the world. That is our fate. If the Ministry wants to gloat over having reached a produticon figure which we had

[Shri D. D. Desai]

done 10 years back, I think, it would be a misfortune for our country. During all this period, we have learnt only a little and we have to improve ourselves a great deal and not be satisfied with the limited achievement of recovering from the past shortfalls in production.

One feature which the Ministry has felt is that discipline has brought a certain amount of increase in productivity. It is true. But if a person is performing his duty or doing the work for which he is paid, is he doing some obligation to the Government? Is he doing something special for the country? In the Ministry's Report, there is a mention about workers' participation in management and all that. Where is the consumer? The consumer is being fleeced. He has to pay higher prices today. We might claim that high cost of steel plants is responsible for that. I would say, why should we at all pay or have the cost of steel equipments production more than Rs 4,000 to Rs. 5,000 a tonne Our growth is inhibited because of the high cost of plants, machinery and equipments, whereas steel used does not cost more than Rs 2000 to Rs. 2200 a tonne? I would strongly urge upon the hon. Minister that he should insist on the Department to produce designs which will eliminate many of the processes and which will reduce the cost.

The direct reduction process is already established. There is no use of having or relying on only LD process. That is over 20 years old. The Minister should know it. He should do something in this direction.

I had a hand in some of the negotiations for setting up these plants in 1953-54. From 1948 onwards, the Government of India had been having negotiations with Japan for setting up of steel plant. But no result was achieved. After the negotiations in Germany with Demag, Krupps, Dr. Schatt and others, the proposals were finalised and they were handed over on a platter to the Government which now forms the core of the Rourkela plant. The same is the story of the Durgapur plant and the Bhilai plant. All these steel plants were negotiated by private citizens of India. If that is so, why has the Ministry not so far been able to go into this field where it could do far better?

They are talking about friendship with the Soviet Union. We like it. All the same, we must realise that the Soviet Union was primitive when India was a highly developed country in steel-making. To go with a begging bowl round the world for technology is a shame for this country and I would urge upon the Ministry that we should not do it under any circumstances. Whether it is Japan or Soviet Union or USA or UK or Germany, it does not lie in our heritage to go round the world with a begging bowl. Our forefathers must be feeling dejected at seeing that we people are going round the world for borrowing technology which we have been having for thousands of years.

There is the direct reduction method. Why should we not use it? Why should we not cut the cost of our steel plants? They are giving the figures of increased tonnage by producing more of heavier sections which sometimes nobody wants and these things lie in the stockyards for years together. The country is investing a lot of money on heavy steel plants at a great cost (and sacrifice) to poor people There are the States like, Bihar, Orissa and Madhya Pradesh which have tremendous resources of iron ore It is our duty to see that none of the States suffers...

MR. SPEAKER: Do you mean to say that the direct reduction method will bring down the capital cost?

SHRI D. D. DESAI: Yes; and not only the capital cost but other costs also.

MR. SPEAKER: By how much?

SHRI D. D. DESAI: By about 30 per cent. Steel production methods have completely changed during the last 20 years. If more information is required, I can give it.

I have great respect for the Minister and I think these are things that would pain and prick him, and he would take necessary action. He will definitely fare better in the operation, now that he knows what some people feel.

We have talked about some other matters like aluminium. We had licensed Bharat Aluminium Co., to go into production many years ago but, unfortunately, it dragged its feet. Whatever the reasons, the Minister may look into them and find out why they did not go into operation.

The same is the story of Khetri.

Then, we have taken over the Debari Zinc Smelter plant from a private party but, here again, the production is falling occasionally and it stops production altogether sometimes.

These are things which should be considered and we should not delude ourselves into a sense of complacency that we are more fortunate now and the country is on its way to prosperity. It is not so the true picture is that we have invested constly resources and we have not been able to make the most of them. We should, under all circumstances, get the best out of our resources. In this matter also, I would add that the Minister may draw his own conclusions. It is not a question of the public sector or the private sector, he can draw up his own balance-sheets—given the resources in one area and given the same resources in another area, which is yielding better results. He can then check easily as to which gives greater benefits. After all, whether it is X, Y or Z, they are all citizens of the country and the Government is also an elected Government. Therefore, they are not dealing with a third party; it is Indians dealing with Indians.

So, I feel strongly that, based on the economics, it should be decided as to which one should be preferred, and in preference to what.

Now, I do not know whether the Minister is seized of the matter of developing Titanium and so many other metals which ore necessary for our defence. Our country's slavery had its origin in not utilising our resources. China invented explosives and India invented steel, but both countries became slaves of other countries. Neither the European countries nor the other western countries had any contribution to make in either of these areas, but today, they are dominating and we have become slaves of these people. It is all because of not utilising our own resources. Today we are talking about developed countries, imperialism and all that. But we should have given thought to our own limit operations and failings and not making the most of the resources available to us.

SHRI PRABODH CHANDRA (Gurdaspur): The slogan that caught the imagination of the English nation during the Second World War was, 'how few, for how many and how much'. This referred to the part played by the Royal Air Force during the Second World War, meaning thereby that a few people of the Royal Air Force had done a tremendous work for a good number of the English people. There was a feeling that the English people would have to run to Canada to save their children and save themselves. But it was the Royal Air Force that saved England and the English nation. Similarly, the same thing can be said about our Minister Shri Charanjit Yadav. He, with a few devoted workers, has been able to do wonders in the production of steel. The few minutes that are given to me, I would not like to waste in praising too much my friend, Shri Charanjit Yadav, but the country owes a great debt of gratitude to him for the progress he has made in the steel industry.

[Shri Prabodh Chandra]

But, along with the progress in the production of steel, arises the probelm of export of steel to other countries. I am ashamed to tell you that, during the last ten years, on every tonne of managanese ore that we were exporting to other countries, India was losing about three dollars; though we earned some foreign exchange, actually, taking into account the cost of excavation of the manganese ore and the other things, we were losing. Most of the countries that imported the manganese ore put a clause in the agreement that the manganese ore would be imported in their ships. I shall give an instance. A few hundred tonnes of manganese ore were exported to Japan; it was below the grade of 50 per cent agreed to under the Agreement; the Japanese, instead of asking our Commercial Attache to come and examine it and either throw the ore in the sea or keep it aside, sent back that ore to Goa and charged the Government of India the freight for sending that ore back to India. Therefore, I would like to emphasize with all the force at my command that we should try to see that most of the ore or steel that is exported to other countries is exported in our ships. For that, there should be some cooperation between the shipping industry and the iron and steel industry. Previously we used to find fault with one or the other: there was no coal and, therefore, there were no railways and, therefore, steel could not reach. Now we have the steel to export, but we do not have ships to export the steel to other countries. Therefore, one thing that I would like to emphasize with all the force at my command is that, along with increase in the exportable steel, the Shipping Ministry should see to it that we have enough ships to export our steel to other countries.

Another point that I would like to make is this. In the contract with the Japanese about export of manganese ore, we did not put a clause that the price of manganese ore would depend on the price in the world market. The Japanese were clever enough to delete this clause; our officers were humoured by those people and they did not put that clause that the price in the world market would be the criterion for deciding the price of the managanese ore that was being sent from India. Therefore, while entering into agreements with other countries, we should have a clause that the price of the Indian steel would depend on the price of the steel that would be prevailing in the world market.

As Mr Desai has said, if somebody is doing his duty in India, we feel that he is doing very much. This is because of the fact that all the people here do not do their duty. About 20 years back, I was asked to take an American delegation to some of the officers. I introduced one officer saying that he was a very honest officer. Immediately one of the Americans said, "It seems, honesty is a rare commodity in India; after all, honesty is the least that can be expected of an officer, therefore, why should you emphasize that he is an honest officer? If he were not an honest officer or a good officer, he would have been removed from service. So, why should you emphasize that he is an honest officer?" But emphasising in one case that he is a good officer means that 99 out of 100 are not honest. We lay too much emphasise when somebody is doing his duty. We are paid for it, the workers are paid for it and the officers are paid for it; we must do our duty. I would request the hon. Minister to see that there is some co-relation between production and the wages.

Now, it is because of the emergency, it is the fear complex that is responsible for some of us doing our duty, it is not because the character of the people has changed. Now if there is a queue for the bus, we say that emergency is responsible for this discipline. Queue is the leost thing that is expected of everyone. Why should any person force himself before others? I would request that we must emphasise on the fundamentals. These are very small things in the life of a nation, in the history of a nation and we must try to do something which is extraordinary and which is not expected

from an average man. Now, we try to buy the loyalty or the honesty of the people. If a policeman catches a dacoit, he is offered Rs. 2,000; if somebody does his duty, he is given an increment. The officers, therefore, feel that it is only the money that can make them do their duty.

Another point that I would like to emphasise is that while in the case of TISCO, the production is hundred percent, in the case of our public sector companies, it is 80 per cent or 60 per cent; average 69 per cent. As compared to our public sector companies, the TISCO machinery is a junk. Their machinery does not compare with what we have in the public sector units. When TISCO can produce hundred percent, why can't our plants not produce 100 per cent?

MR. SPEAKER: In respect of Bhilai, it is 102 per cent.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI CHANDRAJIT YADAV): 112 per cent.

SHRI PRABODH CHANDRA: Let us hope for the best

The other point that Shri Desai mentioned was that the construction cost for steel per tonne in India is the highest in the world. Even the Americans who are known for spending too much spend much less; the Japanese spend the least. We spend much more in setting up a plant as compared to other countries. There is a strange thing; the Japanese import raw material from India and after manufacturing steel, they export the same to other countries of the world at much cheaper price than what we can afford to do. We should, therefore, try to cut the production cost of steel. On the one hand, we say that the private sector units should bring down the prices, but there appears a news simultaneously that the price of the steel in the Government sector plant has gone up by Rs. 300 per tonne. People laugh at it. The Government should be an ideal entrepreneur. The public sector units should set an example before the private mill owners so that the people may see that Government sector is doing much better than others. While we increase the price in public sector units, we expect the private mill owners to reduce the price

Then, when we set up a steel mill, we always try to construct the officers' quarters first, dinning halls, their clubs bungalows etc. I would like to impress on the Minister, who is of a socialistic mind, that we should try to build the houses of the workers first At the moment, there are only 60 per cent workers who are provided with houses. In many cases, only 40 per cent of the workers have been provided with accommodation. The maximum housing capacity that we provide for workers is 60 per cent. The others are left to find a place for themselves. I would, therefore, urge once again that we should try to build houses for the workers first and then for the others.

With these words, I congratulate the Minister for good work and support the Demands of the Ministry.

डा० गोविन्द दास रिछारिया (झांसी): इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं माननीय यादव जी तथा उनके सहयोगी श्री सुख देव प्रसाद जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए तथा अथक परिश्रम से और लगन से इस्पात का उत्पादन बढ़ाया है जिससे न केवल जितनी देश की आवश्यकता थी वह पूरी हुई बल्कि विदेशों को भेज कर उससे विदेशी मुद्रा भी उन्होंने देश के लिए कमाई है।

इस मंत्रालय के द्वारा इस्पात के अलावा ताम्बा, सीसा और दूसरी जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी खोज जोरों से की जा रही है। देश की भूमि के नीचे जो सम्पत्ति छिपी पड़ी है उसको निकाल कर राष्ट्र के निर्माण में, उसके विकास में तथा देश को स्वावलम्बी बनाने के क्षेत्र में सब से अधिक कार्य यही मंत्रालय कर रहा है। मैंने स्वयं देखा और पढ़ा है कि यादव

[डा० गोविन्द दास रिझारिया]

जी दूर दूर के क्षेत्रों में जहां खोज चल रही है चाहे हिमाचल के पर्वत हो या मैदान हों या जंगल हों वहा स्वय जा कर अपने विशेज्ञों से बात करते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं और न केवल उनकी कठिनाइयां दूर करते हैं बल्कि उनका पथ प्रदर्शन भी करते हैं। इस प्रकार से छिपी सम्पदा को निकाल कर वह राष्ट्र के निर्माण में, उसके विकास में तथा राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाने में भारी योगदान कर रहे हैं।

बुन्देलखड बहुत पिछडा हुआ क्षेत्र हैं। ललितपुर में जा कर उन्होने स्वयं अपने विशेज्ञों से बात की है। उस क्षेत्र में ताम्बे की खोज हो रही हैं। वहा पर युरेनियम भी मिलने की आशा है। इस प्रकार की रिपोर्ट आपके विशेषज्ञों ने दी है। मेरा आप से निदवेन है कि ज्यादा विशेषज्ञ वहा पर आप नियुक्त कर, ज्यादा आर्थिक मदद दे कर वहा जो सम्पत्ति छिपी हुई है, उसको निकलवाने की कृपा करें। वह क्षेत्र बहुत बाहदुरो का क्षेत्र है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में वह पिछड गया हैं। जो खोज कार्य चल रहा है उससे उन लोगों मे आशा बधी है, आशा की किरण का उनके मन में सचार हुआ है। यह भी खबर मिली है कि वहा लोहा भी निकलने की आशा है। मेरा निवेदन है कि वहा जो जो निकलने की आशा है खोज करवा करके जल्दी उसको आप निकलवाने की कृपा करे। जो कुछ वहा निकले ताम्बा निकले, सोना निकले या कोई और खनिज पदार्थ निकल उसका प्लाट भी वहा लगवाने की आप कृपा करें।

विन्ध्याचल पहाड़ियां जोकि बुन्देलखंड में आती हैं वहा भी सर्वे कराने की आवश्यकता है। चाहे उसका आप हवाई सर्वे कराएं लेकिन उसका एक डिटेल्ड सर्वे जरूर आपको करवाना चाहिये। बादा जिला बुन्देलखड का ऐसा है जहा बहुत से खनिज पदार्थ मिल सकते हैं। ललित पुर भी है। वहा पर भी कई चीजें मिलने की आशा है। बहुत पहले एक गांव है सिंधवाहा जहां सोना निकला था। उसको भी दिखवाने की आप कृपा करें। पूरे जिले का पहले आप हवाई सर्वेक्षण कराएं और उसके बाद डिटेल्ड सर्वे कराएं तो बहुत सी चीजे आप बुन्देलखड क्षेत्र में पहाड़ों के नीचे मिल सकती है जिससे आपको राष्ट्र निर्माण में बहुत मदद मिल सकती है। अच्छे अच्छे खनिज पदार्थ वहा मिलने की आशा है। इनके कुशल नेतृत्व और पथ प्रदर्शन में जो कार्य चल रहा है और जिस तरह से इस्पात के मामले में इनके विभाग ने तरक्की की है उसका उत्पादन बढ़ाया है उसी तरह से आशा है कि दूसरे खनिजों के मामले मे ताम्बे आदि के मामले में भी ये देश को स्वालंम्बी बनाने में सफल होगे। मैं समझता हू कि आपके ये प्रयास जल्दी सफल हो सकते हैं यदि आप ज्यादा विशेषज्ञ लगा कर इस चीज को पूरा करने की कोशिश करे। इस कार्य में बुन्देलखड की भूमि आपकी मदद करेगी, आपको सहयोग देगी, वहा के लोग देगे।

इन शब्दो के साथ मैं इन मागो का समर्थन करता हू।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इन ग्रान्टस पर दो, तीन बात कहना चाहता हूं। इससे पहले माननीय सदस्य ने जो तमाम बात आपके सामने रखी है, मुझे आशा है मंत्री जी उनका जवाब देगे। मैं खासतौर से 2, 3 बात कहना चाहता हूं।

पबलिक सैक्टर में जो स्टील के कारखाने हैं वहा ट्रेड यूनियन की फंक्शनिंग और यूनियन क अधिकारों को नहीं माना जाता है। वहां पर ट्रेड यूनियन अपना फंक्शन कर सक, इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। इनका फंक्शन वहा के अफसरो पर डिपेंड करता है, जैसा अफसर चाहते हैं, उसी तरह से उनको फंक्शन करना पड़ता है, जिसके लिये बहुत मुश्किलात हो रही हैं। रजिस्टर्ड यूनियन, रिकग्नाइजड यूनियन हैं मगर उनके आफिस

रखने के लिये बड़ी बड़ी पाबन्दी हैं, उनके काम करने के लिये बड़ी बड़ी पाबन्दियां हैं। हालांकि इन तमाम यूनियनों में वहीं के लोग हैं। कोई बाहर का आदमी नहीं है। जो वहां काम करते हैं, वही लोग हैं, वहां के एम्पलाई उसको चलाते हैं, लेकिन उनको अपने घरों पर भी मीटिंग करने की इजाजत नहीं है। अगर मजदूर बातचीत करना चाहें तो उसका भी अधिकार उनको नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो ट्रेड यूनियन के कार्यकर्त्ता को डिसमिस किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है और कोई चार्जशीट भी नहीं दी जाती है। उसकी इन्क्वायरी भी नहीं होती है और उसका समरी डिसमिसल होता है। यह पद्धति वहां चल रही है।

दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और बोकारो सभी जगह इसी तरह की स्थिति है। मैं खास तौर से मंत्री महोदय से कहूंगा कि कम से कम इसकी कोई गारन्टी होनी चाहिये।

आप जानते है कि स्टील के जो कारखाने हैं वह बड़े बड़े एरिया में होते हैं। वहीं पर साथ में ही सब लोग रहते हैं। वहां पर और कुछ नहीं है।

वहां पर शराब की दुकानों की इजाजत तो दे दी जाती है मगर मजदूरों की रजिस्टर्ड यूनियन के लिये इजाजत नहीं है। वे लोग अपने क्वार्टर में भी यूनियन का आफिस रखें, यह भी इजाजत नही दी जाती है। यह कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल गलत चीज है।

मैं खुद भिलाई गया था। कारखाने के गेट के सामने ही कितनी बड़ी शराब की दुकान है। वहा खुलेआम शराब बिकती है, और लोग पीते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड यूनियन हैं, 5,5 बरस से काम कर रही हैं, सभी इस बारे में जानते है। यहां तक भी होता था कि जब कोई डिफिकल्टी अथारिटी को होती थी तो ज्वायन्ट काउंसिल हुआ करती थी, मगर कुछ दिनों से यह तरीका भी बन्द हो गया है। यूनियन को फंक्शन करना मुश्किल हो गया है। उनका आफिस भी नहीं है। कहा जाता है कि अगर आफिस बनाना है तो 5 मील दूर चले जाओं। अब जो आदमी एम्पलाई है, कैसे इतनी दूर काम करेगा, फंक्शन करेगा? कैसे वहां पर लोगों की ग्रीवान्सेज को रिप्रीजैंट किया जायेगा। वहां पर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि एमरजैंसी मे ऐसा हो गया है, इसके पहले भी यही हालत थी।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि कम से कम वे इसका जवाब दें और ऐसा कुछ करे जिसमें यूनियन वहां फंक्शन कर सके। मान लिया कि यूनियन को रिकगनाइज नहीं किया है मगर ट्रेड यूनियन एक्ट के मुताबिक अगर युनियन रजिस्टर्ड हो तो उसको थोड़ा बहुत तो अधिकार होता है। वह अपने अधिकारो को किस तरह से काम में लाये?

आप कहते हैं कि एम्पलाई ही यूनियन को मैनेज करेंगे। लेकिन अगर एम्पलाई खुद चलाते हैं तो उनको भी यह अधिकार नहीं कि वे बैठकर मजदूरों की बात सुन ले और कुछ कर सके। ऐसे किस तरह से काम होगा।

13.00 hrs

जे० के० नगर के बारे में मैं आपसे यह कहूंगा कि कई बार उन लोगों से आपने बातें की हैं। सन 1973 से वहां पर लाक आउट हुआ है। आज सन् 1976 चल रहा है। तीन साढ़े तीन साल से लोग बेकार है। लोगों के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। उसका इन्वेस्टीगेशन हुआ, उसकी रिपोर्ट आई। उसकी खबर हमें भी मिली, अखबारों में भी रिपोर्ट आई, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ एक डैपूटेशन भी मंत्री जी से मिला था, आपने उससे वायदा किया कि यह कारखाना गवर्नमेंट ले लेगी लेकिन एक बरस हो गया, यह बात भी पूरी नहीं हुई। उसके बाद यह हुआ कि गवर्नमेंट नहीं लेगी। उसके बाद कहा गया

[श्री मोहम्मद इस्माइल]

कि कम्पनी उस को लेगी। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कम्पनी के मिसमेनेजमेंट और धांधली की वजह से कारखाना बन्द किया गया है। इस के बावजूद कम्पनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि कारखाना उस को दिया जा रहा है और गवर्नमेन्ट उस को रुपया भी देना चाहती है उस कारखाने की मशीनों को तीन चार बरस से कोई साफ नहीं कर रहा है और वे खराब हो रही हैं। इस बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है। यह बिलकुल गलत बात है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इस सदन में साफ तौर से इस बारे में वक्तव्य दें, ताकि मजदूरों को कम से कम यह तसल्ली हो कि मंत्री महोदय ने सदन में वक्तव्य दिया है और भविष्य में उन की हालत में कुछ सुधार हो सकेगा। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इन बातों के बारे में जरूर जवाब दें।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदन ने मिनिस्ट्री आफ स्टील एंड माइन्ज की एचीवमेंट्स को मुक्त कंठ से सराहा है। इस मिनिस्ट्री ने जो भी कामयाबी हासिल की है, उसके लिए माननीय सदस्यों ने इस मिनिस्ट्री को और मुख्यतया मंत्री महोदय तथा अधिकारियों को, बधाई दी है। उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं।

13.01 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क खास तौर से इस्पात पर निर्भर करता है, क्योंकि उसकी बहुत सी आवश्यकताएं इस्पात से पूरी होती हैं। यदि किसी देश का इस्पात का युटिलाइजेशन कम हो जाता है, तो यह समझा जाता है देश संतोषजनक ढंग से तरक्की नहीं कर रहा है। हमारे देश में इस्पात उद्योग और उसका प्राडक्शन जिस तरह से बढ़ा है, उसको देख कर ऐसा लगता कि उसका भविष्य और भी उज्ज्वल है। पूरा मंत्री मंडल इसके लिए सतत प्रयास करेगा और माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बराबर कोशिश करता रहेगा।

मैं अधिक डिटेल में न जाकर माइन्ज के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस मंत्रालय ने इस्पात की तरह माइन्ज और मेटल्ज के सम्बन्ध में भी काफी तरक्की की है। अगर एक तरह से हम इसको मेटल वर्ष भी कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। पहले कापर, एल्युमिनियम, लैड और जिंक आदि मेटल्ज की गति इतनी धीमी थी कि ऐसा लगता था कि शायद उनका भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। लेकिन हमारे अधिकारियों ने जी जान से प्रयास किया और सब लोगों ने मिल कर एक ऐसा वातावरण पैदा किया जिसमें हम मेटल्ज के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सके हैं।

जहां तक एल्युमिनियम का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि हम अपनी क्षमता का 80 परसेंट उत्पादन कर रहे हैं। यह हमारा एक आल टाइम रिकार्ड है। पिछले साल उसकी डिमांड बढ़ी हुई थी, और लोग उस के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। लेकिन आज हालत यह हो गई है कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के बाद हमारा एल्यूमिनियम बचा रहता है। कमर्शियल ग्रेड और ई० सी० ग्रेड दोनों प्रकार के एल्यूमिनियम आज पूरी तरह से उपलब्ध हैं, जिससे हम यह

आशा कर सकते हैं कि हमने एल्युमिनियम में आल टाइम रिकार्ड कायम किया है।

पिछले साल जैसा कि आपको रिपोर्ट से पता होगा एल्युमिनियम को हम इम्पोर्ट करने के चक्कर में थे। हम इस हालत में थे कि करीब 22 करोड रुपए का एल्युमिनियम हम बाहर से इम्पोर्ट करेंगे। आज हमारी यह हालत है कि हम उस एल्युमिनियम को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और करीब 20 हजार टन एल्यूमिनियम तो हमने एक्सपोर्ट किया है। हमारे एल्यूमिनियम प्लांट ज्यादातर निजी क्षेत्रों में हैं। हमारा एक ही एल्युमिनियम प्लांट पब्लिक सेक्टर में है कोरबा का जिस ने कि अपने पहले ही साल में उसका फर्स्ट फेज जब कि इनागरेट हुआ तभी उसने इस तरह का उत्पादन शुरु किया कि जिस को देख कर देश को उस पर गर्व हो सकता है। उस उत्पादन में करीब 80 प्रतिशत ई० सी० ग्रेड था। उसमें 80 प्रतिशत देश की आवश्यकता का उस ने पहले ही साल में पूरा किया। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहां के अधिकारियों और वर्कर्स ने मिल कर जो ऐसा सद्प्रयास किया है उसके लिए वे सब के सब बधाई के पात्र हैं। हमारा प्रयास यह है कि हम मेटल के मामले में जहां तक हो सके आत्म निर्भर बन सकें।

कापर के मामले में इतना ही कह सकता हूं कि अब तक हम कापर के लिए बाहरी मुल्कों का मुंह देखते रहे लेकिन अब खेतरी का कापर प्रोजेक्ट जब अपने प्रोडक्शन में आ गया है तो हमने कापर काफी मात्रा में पैदा किया है और आज हालत यह है कि हम अपनी आवश्यकता का बहुत सा हिस्सा वहीं से पूरा कर सकते हैं। मलाजखंड की चर्चा भी सदन में हुई है। वह योजना सरकार ने ले ली है, उसका डी० पी० आर० तैयार हो चुका है और वह सरकार को मिल चुका है।

श्री दामोदर पांडेय : बड़ी धीमी गति से चल रहा है।

श्री सुखदेव प्रसाद : जैसी कि देश कि स्थिति आप को पता है उसको देखते हुए धीमी गति तो नहीं कही जा सकती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए तथा और सब बातों को देखते हुए। इतनी सी बात मैं जरूरी कहूंगा कि जब हम इस प्रोजेक्ट को लेने जा रहे हैं तो जरुरी है कि उसका डी० पी० आर० हो, उसकी स्टडी हो, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स किसी नतीजे पर पहुचें, तब जाकर हम प्रोजेक्ट शुरु करने की स्थिति में होते हैं। जल्दी में गडबडी हो सकती है। इसलिए कदम कदम पर वाच करना पड़ता है।

श्री दामोदर पांडेय : इस पर पैसा और खर्च करने की आवश्यकता है।

श्री सुखदेव प्रसाद : अभी तक जितनी आवश्यकता पैसे की इस योजना के लिए रही है उसके लिए पैसा दिया जा चुका है। आगे जैसी आवश्यकता होगी और ज्यों ज्यों पैसे की स्थिति आएगी, पैसा दिया जाएगा। देश की वित्तीय स्थिति सुधर जाएगी, तो पैसा भी गवर्नमेंट देती जाएगी।

SHRI D. D. DESAI: May I request the hon. Minister to utilise the Earth Resources Trekking, Sitlitu Systems, namely, ERTS I and ERTS II, which would provide compete map of all the mineral resources of the coutnry. Photos from both these satellites are available against a request with a small fee.

श्री सुखदेव प्रसाद : अभी माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर संकेत किया उसके संबंध में मैं इतना ही इशारा कर सकता हूं कि जो हमारे रिसोसज हैं जैसे कि जी० एस० आइ० है या मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन हैं, या आई० बी० एम० इंडिया ब्यूरो आफ़ माइन्स हैं उसके जरिए हम अपने मिनरल रिसोर्सेज का पता लगा रहे हैं और नई टेक्नोलोजी जो भी आती जाएगी उसका भी हम इसके लिए उपयोग करेंगे । जैसे जैसे हमको आवश्यकता पडेगी जो भी नई टेक्नोलोजी मिलेगी उसका हम उपयोग करेंगे ।

अभी एक माननीय सदस्य ने टुंडू लेड स्मेलटर का जिक्र किया था । टुंडू लेड स्मेलटर की क्षमता 3600 टन की है । 8000 टन तक की क्षमता तक बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है । पार्टली इसको कुछ क्षमता बढ़ा भी दी गई है और इस साल करीब 5000 टन लेड का उत्पादन हुआ हैं । यह बहुत बड़ा एचीवमेंट है । इस तरीके से मैं समझता हूं लेड के मामले में हम काफ़ी आगे बढते जा रहे हैं ।

जहां तक वाईजैक लेड स्मेलटर की बात है, उसकी क्षमता 10000 टन की है । लेकिन एक बात है कि वहां पर जो हम स्मेलटर लगाने जा रहे हैं उसके लिए कन्सेन्ट्रेट भी दूसरी जगहों से लेना पड़ेगा जैसे कि मचिया, बेलारिया और अग्निकुण्डला– इन जगहों से लेना पड़ेगा लेकिन इसमें थोड़ी सी देरी है । जब यह बनकर तैयार हो जाएगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां उत्पादन शुरू हो जाए । इसके अलावा वाइजैक पल्प्यूरिक एसिड प्लान्ट की भी योजना है । स्मेलटर से जो भी सल्फ़र आक्साइड गैस निकलती है वह बेकार चली जाती है । इसलिए उसको इस्तेमाल करने के लिए एक सल्प्यूरिक ऐसिड़ प्लांट लगाने का विचार है । गवर्नमेंट ने इसके ऊपर विचार किया है और इस तरह से हम उसका पूरा उपयोग करना चाहते हैं ।

इसी प्रकार से हमारी जितनी भी माइन्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं उनमें हमारी दिन प्रति दिन तरक्की होती जा रही है । हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं । जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे हम आगे और भी हिम्मत से काम करते जाएँगे ।

श्री दामोदर पांडेय : आयरन ओर के मामले में जो अलग अलग ढंड से काम चल रहा है उसके बारे में भी एक मैनेजमेंट और नेशनलाईजेशन के लिए भी क्या सरकार ने कोई निश्चित मत बनाया है ।

श्री सुखदेव प्रसाद : जहां तक आयरन ओर का सम्बन्ध है, हमारे सीनियर कलीग, माननीय यादव जी उसका जवाब देंगे । मैंने तो यहां पर जो माइन्स और मेटल्स की बातें उठाई गई उनका तजकिरा किया ।

श्री मोहम्मद इस्माइल : बाकुंडा में वूलफ़ेम माइन्स जो हैं उनके बारे में भी बताइए ।

श्री सुखदेव प्रसाद : : वूलफ़ेम माइन्स एक प्राईवेट माइन्स थी । बीस साल तक इसका कांट्रेक्ट रहा है । वह कांट्रेक्ट अब समाप्त हो चुका है जिसके लिए उन्होंने फ़िर से एप्लाई किया था । लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके पास तमाम रायल्टी का बकाया पड़ा है जिसके कारण फ़ैसला उनके पक्ष में न हो सका । अभी तक जो वूलफ़ेम का प्रश्न रहा

है उसमें जो वे वहां पर लोकल लेबर को इस्तेमाल करते रहे हैं, आपको जानकर महसूस दुख होगा कि जो पुरुष काम करते रहे उनको केवल दो रुपया प्रति दिन की मजदूरी दी जाती रही। इसी प्रकार से जो वहां पर स्त्रियां काम करती रहीं उनको केवल 1 रुपया और 25 पैसे मजदूरी दी जाती रही।

SHRI S. N. SINGH DEO (Bankura): Wolfram is a very strategic mineral. So far as I know, all the run of the mines is being exported. Is there any programme to utilise it locally in our ammunition factories and other units so that this strategic mineral, which is very rare, could be utilised in our own country?

श्री सुखदेव प्रसाद : जहां तक टेक ओवर या नेशनलाईजेशन की कार्यवाही करने का सवाल है जहां तक वूलफ्रेम माइन्स की बात है वह कोई बहुत बड़ी माइन नहीं है। वह छोटी सी माइन है। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो अपनी इच्छा व्यक्त की है उसपर विचार करेगी। यदि यह वायबिल हुआ और नेशन के हित में होगा तो सरकार उसपर जरूर विचार करेगी। लेकिन इस समय मैं कोई आश्वासन देने में असमर्थ हूं। मैं इस तरह का कोई आश्वासन इस समय नहीं दे सकता हूं।

इस माइन में सब की सब लोकल लेबर हैं, कोई भी इस तरह का नहीं है जो परमानेन्ट नेचर का हो। इस माइन का मामला सरकार के विचाराधीन है।

जहां तक लेबर रिलेशन्ज का सवाल है सरकार उनके बारे में पूरा ध्यान दे रही है। स्टील प्लांटस में आप जानते हैं मिनिस्ट्री ने काफ़ी ध्यान दिया है—शाप-लेवल तक वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कर दिया गया है, जिसके अच्छे परिणाम निकले हैं। वर्कर्स भी बहुत खुश हैं। दूसरे कारखानों में भी ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास हो रहा है। खेतड़ी में कुछ दिक्कत पैदा हुई है—वहां दो यूनियनों का झगड़ा है, जिस की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका है, लेकिन उस पर भी विचार किया जा रहा है।

जहां तक वर्कर्स को फ़ैसिलिटीज दिये जाने का सवाल है—जितनी भी फ़ैसिलिटी दी जा सकती है, चाहे वह किसी भी किस्म की माइन हो, वह हम प्रोवाइड कर रहे हैं।

श्रीमन, अन्त में जिन माननीय सदस्यों ने हमारे मंत्रालय के कार्यों के लिए धन्यवाद दिया है, हम उन के निहायत कृतज्ञ हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी मिनिस्ट्री उनके विश्वास को लेकर आगे बढ़ेगी और अधिक से अधिक कामयाबी हासिल करेगी।

श्री सी० डी० गौतम (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। साथ ही मंत्री जी, उन के सहयोगी और उन के अधिकारी गणों को बधाई देता हूं—इसलिये कि उन्होंने अपने मंत्रालय के हर क्षेत्र में काफी प्रगति की है।

परन्तु, श्रीमन्, जहां तक मेरे जिले का सम्बंध है—बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में है, वहां मलन्जखण्ड की ताम्बे की खान के बारे में मंत्रालय ने अभी तक बहुत थोड़ा काम किया है। यह काम 1968 में प्रारम्भ हुआ था वहां कुछ छिद्र बनाये गये—टेस्टिंग के लिये यह मालूम करने के लिए धातु की क्वालिटी कैसी है और पाया गया कि वहां पर बहुत बढ़िया धातु के डिपाजिट्स हैं। 1970 में, जब माननीय नीतिराज सिंह जी केन्द्र में राज्य मंत्री थे उस समय मैं खुद उन के साथ मौके पर गया

[श्री० सी० डी० गौतम]

था, उस समय हमारे सामने ताम्बे की ऐसी चिप्स निकली जो सोने के समान थी। जिस से यह सिद्ध हुआ और वहां की अथोरिटीज भी कहती हैं कि वहां पर बहुत बढ़िया डिपोजिट है उन का अनुमान है कि उस में 50 मिलियन टन धातु है। उस के बाद काम तेजी से नहीं हुआ, अगर सरकार चाहती तो हो सकता था। हमारे मंत्री जी यहां बैठे हैं, उदाहरण के लिये मैं मैंगनीज-ओर इण्डिया लि० का जिक्र करना चाहता हूं। आप को याद होगा यह कम्पनी बिलकुल घाटे में चल रही थी, इस पर बहुत कर्जा हो गया था, माल बिक नहीं रहा था और एक समय ऐसी स्थिति आ गयी थी कि उस को बन्द कर दिया जाय। उस समय हमारे मंत्री मालवीय जी ने एक सबकमेटी मुकर्रिर की और कुछ आफिसर्ज को बैठा कर विचार किया। बाद में उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस पर निर्णय लिया गया। उस के दो साल बाद उसी मैंगनीज और इण्डिया लि० की स्थिति सुधर गई। जहां मजदूर को देने के लिये पैसा नहीं था, वहां उन के वेतन भी बढ़ गये। तो सरकार अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हर तरह से सरकार साधन जुटा सकती है।

अब मैं कुछ मलन्द खण्ड और खेत्री के बारे में कहना चाहता हूं। खेत्री अन्डर ग्राउन्ड वर्क है, वहां पर मजदूरी बहुत महंगी है और मलन्द खण्ड बिल्कुल ओपिन कास्ट है इसलिये वहां पर खेत्री के मुकाबले आधी मजदूरी में काम हो सकता है। मलन्द खण्ड में डिपोजिट 1.37 परसेंट है जब कि खेत्री में 1 परसेंट या उस से भी कम है। मतलब यह कि हर तरह से खेत्री मलन्द खण्ड के मुकाबले में कम दर्जे में बैठता है। लेकिन चूंकि वहां पर 100 करोड़ के करीब खर्च कर चुके हैं इसलिए वहां तो काम चालू रहेगा ही। परन्तु उस से अधिक डिपोजिट वाली माइन्स में, जो कि मलन्द खण्ड में है काम चालू नहीं हुआ है। मेरी मांग है कि वहां काम चालू किया जाय। हमने ऐसा सुना है कि जब मलन्द खण्ड चालू होगा तो वहां का माल खेत्री ले जाया जायगा और छोटी बड़ी माइन्स का भी ले जाया जायगा। तो आप ने कभी यह सोचा कि वहां का माल खेत्री ले जाने में कितना महंगा पड़ेगा? मलन्द खंड का माल अगर ले गये तो आप को 1250 किलो-मीटर उस को ले जाना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर कितना खर्चा पड़ेगा। हमने पूछा था कि, 10 साल में यह जो खर्चा होगा उतनी रकम में मलन्द खण्ड में स्मैल्टर लग सकता है? तो उस समय के मंत्री स्वर्गीय श्री कुमार मंगलम ने कहा था कि हां लग सकता है। जब ऐसा हो सकता है तो सरकार यही योजना क्यों नहीं चालू करती? आप मलन्द खण्ड मैं स्मैल्टर लगाना शुरू करें। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर 80 मिलियन टन तक माल है। इसलिये सरकार इस ओर खास तौर से ध्यान करे और मलन्द खण्ड में स्मैल्टर लगाये और जल्दी से जल्दी काम चालू करे।

एक सुझाव यह है कि खेती करने वाले लोगों को कूआ बनाना पड़ता है, मकान बनाना पड़ता है जिस के लिये आज उन को कोयला नहीं मिलता। पहले जब जंगलों का सरकारी-करण नहीं था तो वह लोग जंगल की लकड़ी से कोयला बना लेते थे। लेकिन आज उन को कूए के लिये कोयला नहीं मिलता है। इसलिये मेरी मांग है कि हर एक जिले में स्टाक रखा जाय कोयले का जो किसानों को उपलब्ध हो सके।

मैंगनीज ओर के जो मजदूर हैं वह पहले स्ट्राइक पर जाने वाले थे। परन्तु हमारे उपमंत्री महोदय उस वक्त गये थे और मैं भी उन के साथ गया था और मजदूरों को स्ट्राइक पर जाने से रोका गया। उनको समझाया गया कि जिसकी वजह से वह स्ट्राइक पर नहीं गये। उस वक्त उन को 4 रु० मजदूरी मिलती थी। मैं मंत्री

महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उन की मजदूरी 5.80 पैसा कर दी है। मजदूरों की यह भी प्रार्थना है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, प्रोफिट्स बढ़ेंगे, उन की मजदूरी में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उन की यह मांग उचित है और इस को सरकार को मान लेना चाहिये।

हमारे यहां पर ताम्बे की माइन्स और भी हैं, मलन्द खण्ड से थोड़ा आगे। मालूम नहीं विभाग ने उस का सर्वे किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि उस सर्वे किया जाय।

और एक हमारे यहां सोन नदी है, उस मे पुरातन काल से सोना होता था, और वहां पर सोनझरे लोग काम करते थे, सोन नदी की रेती में से सोना निकाल कर बेचते थे। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ख्याल करे और रिसर्च करे। मेरा ख्याल है कि वहां पर हम को सोना जरूर मिलेगा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस्पात और खान मंत्रालय ने जिस तेजी से काम किया है, उस का लाभ श्री चन्दूलाल चन्द्राकर उठाएंगे। इन की सीट तो सटेन हो गई क्योंकि आज सारे मजदूर खुश हैं, सारी दुनिया खुश है और हिन्दुस्तान का हर एक आदमी खुश है। आज स्टील का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया है और यह भी आश्चर्य की चीज है कि श्री सुखदेव प्रसाद, जो कि वयोवृद्ध हैं, भी बड़ी तेजी से बोलने लगे और इनमें आत्मविश्वास जाग गया। जब वे बोल रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे कि एक जवान आदमी भाषण दे रहा हो। तो यह बड़ी बात हुई है और हम तो इन दोनों को धन्यवाद देते हैं। यह दूसरी बात है कि यह हमारे धन्यवाद को ट्रान्सफर कर दें और यह कहें कि यह सब मजदूर का कार्य है और इन के कार्यालय में काम करने वालों का काम है। अब हम ने तो इन को धन्यवाद दे दिया। ये इस का उपयोग कैसे करें ये जानें। मैं यह समझता हूं कि श्री चन्द्रजीत यादव का पहला सेंटेंस यह होगा कि यह सब काम हमारे स्टील प्लान्ट्स में काम करने वाले श्रमिकों का है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: How does Mr. Chandulal Chandrakar come in at this stage?

श्री मूल चन्द डागा : इन्होंने ही तो भिलाई के कारखाने का लाभ उठाया है। इसलिए मैं ने इन के बारे में कहा है। ये यहां बैठे हुए हैं और उपाध्यक्ष महोदय, आप इन के चहेरे की मुस्कान देखिये। जब से चन्द्रजीत यादव जी आ गये है ये बहुत प्रसन्न हो गये हैं और फूले नहीं समा रहे हैं और इन का वजन भी बढ़ गया है। तो एक बात मैं यह कहना चाहता था।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ने एक दफ़ा श्री चन्द्रजीत यादव से प्रार्थना की थी कि जब आप इतना काम कर रहे हैं तो फिर आप बाहर से इम्पोर्ट क्यों करते हैं स्टेनलैस स्टील को। आप कहते हैं कि हमारे यहां स्टील का स्टाक रखा हुआ है। हिन्दुस्तान में बहुत से मिल हैं और काम करने वाले लोग भी बहुत हैं और सारे मिल ओनर्स ने कई बार आप से प्रार्थना भी की है कि व मिनी स्टील प्लान्ट लगाना चाहते हैं। वे यह कहते हैं कि हमें थोड़ा सा निकिल दे दीजिए और हम बढ़िया से बढ़िया स्टील तैयार कर सकते हैं लेकिन उन की बात सुनी नहीं गई। आप के दुर्गापुर में एलाय स्टील पड़ा हुआ है और दूसरी सब जगह पड़ा-हुआ है लेकिन फिर भी आप इम्पोर्ट करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इम्पोर्ट न करें। उन्होंने इस के लिए आप की सेवा में प्रार्थना की है और दरख्वास्तें भी दी हैं और मैं ने भी कहा है कि क्या कारण है कि आप री-रोलिंग इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे है और जो

[श्री मूल चन्द डागा]

काम करना चाहते हैं उन को मौका न दे कर बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। मेहरबानी कर के इस को आप रीकें. तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि आज स्टील बहुत मौजूद है। एक यह बात मैं आप से कहना चाहता था।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि जब मैं माईंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें यह नोट मैंने देखा:

"Production in Hutti during 1975-76 decreased by 8 per cent compared to 1974-75 due to curtailment of production compelled by accumulation of gold stocks with the company."

मेरी समझ में नहीं आया कि हूटी में इतना गोल्ड का स्टाक हो गया कि आप ने प्रोडक्शन कम कर दिया। यह बात मेरी समझ में बहुत कम आई। आप ने नोट में कहा है.

"Production in Hutti decreased by 8 per ent because there was accumulation of gold"

अभी तक मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि वहां की धरती इतना सोना उगलती है और इतना सोना जमा हो गया है कि वहां आपने 8% प्रोडक्शन डिक्रीज कर दिया। यह बात मेरे दिमाग में नहीं बैठी। मैंने भारत गोल्ड माईंस में जा कर खुद देखा है और आज भी मुझे मालूम है कि वहा पर कुछ दादा लोग काम करने वाले है जिस की वजह से अभी तक यह घाटे में चलती है।

"Production in BGML during 1975-76 decreased by 3 per cent compared to 1974-75 due to strike of workmen. .."

एक बात मैं मानता हूं कि इस में यह सवाल है लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि ये जो रीजन्स आप ने दिये हैं उन पर आप गौर फरमाएं और मेरे ख्याल से मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो इस का उत्तर भी देंगे।

तीसरी बात भी आपकी बड़ी सराहनीय है कि आपने स्टील के क्षेत्र में मजदूरों का पार्टिसिपेशन किया। हम समझते हैं कि यह आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। यह आपने नई बात पैदा की है और इसके लिए आपकी पूरी सराहना की जानी चाहिए। यह बात भी आपके महकमे में बहुत मार्के की रही है कि मजदूरों ने इस साल हड़ताल के अन्दर बहुत कम हिस्सा लिया। यह इससे स्पष्ट है कि जहां 1974–75 मे 5,27,766 मेन-आवर्स का लास हुआ था वहां 1975–76 में केवल 41,983 मेन-आवर्स का लोस हुआ यह कितना बड़ा फर्क है और यह बड़ी सराहनीय बात है।

There are at present 343 such committees functioning in the four steel plants under Hindustan Steel Limited (Bhilai 182, Rourkela 68, Durgapur 71, Alloy Steel Plant 22) 27 in Bokaro, 65 in TISCO and 9 in IISCO.

ये जो अचीवमेंट्स है यह इस बात का सबूत है कि श्री चन्द्रजीत यादव का महकमा मजदूरों के प्रति कितना जागरूक है। इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद।

ट्वेन्टी प्वाएंट प्रोग्राम, बीस सूत्री कार्यक्रम में यह बात शामिल है कि जो मजदूर लोग सोना उगलते है, जो मेहनत करके, खून-पसीना एक करके देश को खुशहाल बनाते है, वे प्रबंध मे भागीदार हों। सबसे पहले आपने यह उदाहरण पेश किया है, इसके लिए हम आपकी सराहना करते है। आज भी कई पब्लिक सेक्टर के कारखाने ऐसे है जहां हमें इस मामले में सफलता नहीं मिली है। यह आपका महकमा है जिसने सबसे पहले मजदूरों को प्रबन्ध में भागीदार बनाया। यह बहुत प्रशंसनीय काम है।

मैं एक बात खानों के संबंध में कहना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि राज्यों में खानों की जिस प्रकार की दुर्दशा है, वे उसे भी देखें। राज्यों के पास साधनों की

कमी होने के कारण वहां खानों की दुर्दशा होती है । इन खानों में जो मजदूर हैं, उनकी भी दुर्दशा होती है। मजदूरों का एक्सप्लॉइटेशन होता है । इसको दूर करने के लिए भी आप कदम उठाइये । हालांकि आपने इन खानों में कोआप्रेटिव्ज दे रखे हैं फिर भी वहां मजदूरों की दुर्दशा है । यह भी आप दूर करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ।

बस इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

SHRI CHAPALENDU BHATTACHARYYIA (Giridih): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants for the Ministry of Steel & Mines today which falls within the overall framework of the non-linear, non-homogenous Fifth Five Year Plan conceived in optiomality for performance and growth and the new economic programme of our Prime Minister.

We congratulate Shri Chandrajit Yadav and his colleague who have given context and meaning to the 20-Point Economic Programme. More than anything else, labour participation in industry would be his particular contribution.

On the 1st May, from within a radius of 60 miles, lakhs of workers converged on Bokaro City, when the Prime Minister inaugurated the hot strip mill. It underlined the expectations which have been aroused in the countryside by the introduction of the new technology there. I would humbly point out that Usho Martin Co. in Ranchi has adopted 200 villages and are spreading all over. If the area of Chhota Nagpur has to be rescued from this two-sector economy, these public sector corporations have a clear socio-economic responsibility for the countryside; and they have to go out and adopt villages. You cannot stop with bringing pollution and the pressure of higher prices to the countryside. The entire region of Chhota Nagpur region I come from, is undergoing social tremors, because, of the heavy industrialization programme that is going on there, and the emergence of a two-sector economy and inter-sectoral imbalances. There are promises to keep. So, I submit that it is one of the patterns which can be adopted for wider coverage in and around these public sector undertakings.

Since the time at my disposal is very limited, I would confine myself only to making certain points. As the steel plants are going to be more intensively worked, the necessity for preventive and general maintenance has correspondingly grown. I would request the Minister to keep himself as far as possible fully informed about these aspects of the question. Secondly, MEKON and all the Research, Design and Development departments of the various units like HEC, Britannia, Jessop and Martin Burn should pool their expertise together for the drawing up of blueprints for spares, and should start manufacturing them as a first step towards import substitution and technological independence. Thirdly, the mass micro-innovation which you can call for at the factory or plant level, should be encouraged and effective suggestions of workers in the plants and mines should be rewarded. That would mean extending workers' participation in industry, in a creative sense; and it will open up a new dimension. TISCO has very successfully done it and our steel plants have a leeway to make up; and it will certainly increase productivity in tonnes per man-year. We have some leeway to make up in it also. Since saleable steel is the real index of production and productivity the ratio of such steel to ingot production should be improved. Updating of technology by introduction of thyrester integrated circuit and computerisation, where necessary and possible, for cost-cutting efficiency is urgently indicated. The report at page 26 speaks of the project and

[Shri Chapalendu Bhattacharyya]

performance evaluation on Indian blast furnaces.

I would again ask the question that was asked by my colleague, Shri D. D. Desai: what about the direct reduction process for steel melting developed by the National Metallurgical Laboratory? Where ore we?

In this context, I would refer to what Mr. Gunnar Myrdal said about the present phase of technology. In steel we have already reached a stage when the old type of steel plant may get out of date and nickel, copper, aluminium and fibre glass will decide the day and they may represent the wave of the future.

The coal dust injection in blast furnace is an important development, and we welcome it. I lay particular stress on the beneficiation plant for low grade ores and minerals as well as the steps to conserve high quality manganese, kyanite and chromite, a lot of which we are now exporting.

The other aspect in which we have to take steps now is recycling for recovery of chrome and nickel. I suggest urgent steps here.

As regards the Five-Year perspective plan for steel making, as I said, after all, so many imponderables have to be assessed, that we should take an in-depth view and draw it up with caution.

I should like the Minister to make himself aware of the state of contract about iron ore. Except Bailadilla, are there any other contracts for the export of iron ore in the order books? When Haldia, Paradip and Vizag Outer Harbour come into operation by tht end of 1976, have we enough orders in the book to fully utilize the extra port handling capacity?

I welcome the apprentices who have been caught young for their assimilation into the emerging industrial culture. But I would urge upon the Ministtr to ensure that the norms are uniformly adhered to in respect of workmen, supervisory personnel and officers in the matter of r cruitment and promotion for their better morale.

Coming to mines, just as higher capacity steel utilisation, in the mineral output also a dramatic change has occurred. But I draw particular attention to the 22° latitude stretching from the Subarnarekha to the Tapti across the Indian continent for intensive investigation in that long stretch of polymetallio mineralised belt. We should concentrate on high-priced minerals like uranium, copper and gold which go together.

There are enormous copper deposits. As regards bauxite, a startling discovery has been made. I congratulate the Minister for bringing about this change in the situation. But there are certain misgivings about the findings of the GSI. What about the geo-physical anomalies in the region stretching from Bakreshwar Hot Springs to Suraj Kund Hot Springs across Pareshnath Hills?

We ore extremely deficient in tin. But there are copper mines at Bargunda and tin mines at Nurungo. There are reports that these were worked and have yielded copper and tin. Since the GSI's survey has proved rather a failure in Nurungo I suggest another look into this region.

Before I conclude, I must again congratulate the Minister for his infusing a new dynamism into the functioning of the Ministry, which has contributed to changing the economic scene, so far as India is concerned.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): I rise to support the Demands of the Ministry.

Recently the Geological Survey of India surveyed the different districts of Orissa, but due to certain reasons,

they have not yet fully explored areas which are far away from the State Capital. The State Mining Corporation had surveyed some parts, but because of the emphasis recently laid by the Government of India on finding mineral resources, Orissa has come into the limelight.

Though there are a large number of mineral deposits in Orissa, the State presents a picture of poverty amidst plenty. Forty per cent of the total area of the State is forest area and there are a number of mineral deposits like graphite, gold, bauxite, chrome and limestone. In Koraput District in particular you will find all these deposits. The Mining Department of the State Government has taken up only one project with the assistance of the Government of India. I am not asking the Minister whether that will be in the private sector or the public sector, but my submission to the Minister is that, since limestone and graphite have already been discovered in this district, their exploitation should be taken up immediately either by the Government of Orissa or by the Government of India.

I have seen the Report of the Ministry regarding bauxite deposits in my district of Koraput You will be surprised to hear that there are huge bauxite deposits particularly in the Panchmali area. I recently visited that area One deposit is about 22 k m long, 3 k.m broad and 60 ft. deep. There are a number of deposits like that in that region, and you will be surprised at the concentration of such deposits in that area The Ministry's Report says that for about 300 miles from Andhra Pradesh up to the east coast of Orissa there are a number of deposits. I am not going into details. Other districts also contain bauxite deposits. So, my submission is that the Minister should consider locating a plant in that area since that circumstances are so favourable. With the present emphasis, I hope more money will also be allocated for further survey.

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर (दुर्ग): जहां कुछ साल पहले इस मंत्रालय में 250 करोड़ का लोहा बाहर से मंगाया जाता था, वहां आज इतना ही नहीं कि काफ़ी लोहा बाहर जाने लगा है कि बल्कि वर्ल्ड टैंडर्ज़ में भारत ने जापान के साथ और ईरान इत्यादि कई देशों के साथ कम्पीटीशन में सफ़लता प्राप्त की है और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ लोहा बाहर भेजा है। खास तौर से कोरिया में जो रेल भेजी गई है वह विश्व में एक ऐसी घटना हुई है जैसी कभी नहीं हुई थी। दुनिया में रेलवे लाइन की लम्बाई 18 मीटर की होती थी। इस कम्पीटीशन में जापान ने यह समझ कर कि हिन्दुस्तान किसी तरह इस में बाज़ी नहीं मार सकता, जब हिन्दुस्तान ने यह दे दिया कि सस्ता और बढ़िया लोहा वह कोरिया को सप्लाई कर सकता है तो जापान ने एक ऐसा दाव फ़ेंका कि जापान ही एक ऐसा मुल्क है जो 25 मीटर की लम्बाई की रेल बना कर कोरिया को दे सकता है .. (व्यवधान) .. । मगर यहां से 25 मीटर की लैंग्थ की रेल का कोरिया को जो निर्यात किया गया वर्ल्ड में उसका रिकार्ड कहीं नहीं है। दुनिया में पहली बार 25 मीटर की रेल बनाई गई और हिन्दुस्तान में वह एक्सपोर्ट हुई।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश ने इस्पात के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। मंत्री जी की विशेष देख-रेख में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और उनकी वैलफ़ेयर की एक्टिविटीज के लिए काफी काम हुआ है। इसके लिए मंत्री जी और मंत्रालय को बहुत धन्यवाद देता हूं।

यह सोचा गया है कि चाहे इस्पात उद्योग हो या और कुछ हो सभी जगह ठेकेदारी प्रथा को बन्द किया जायगा या कम से कम इतना कम कर दिया जायगा कि वह नहीं के

[श्री चन्दू लाल चन्द्राकर]

बराबर रहेगी। इसलिए हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी का गठन हुआ इस कम्पनी ने काम करना भी शुरू कर किया लेकिन आज हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी के जरिये ही सब ठेकों ठेकेदारों को फिर से ठेके दिए जाते हैं। मैं कहूंगा कि ठेकेदारी को कम से कम किया जाए, हो सके तो बन्द कर दिया जाए। ये ठेकेदार और इनके उपठेकेदार दोनों के द्वारा मजदूरों को कई जगह दो रुपये मजदूरी दी जाती है। इस को मंत्री जी देखें कि इतना कम पैसा व क्यों देते हैं।

ताम्बे और टिन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मलाजखंड में काफ़ी ताबा मिला है और उस में तांबा कंटैन्ट बहुत है। मेरा अनुरोध है कि इस के लिए अधिक से अधिक पैसा जल्दी से जल्दी दिया जाय जिस से विदेशों से जो आज भी हमको तांबा मंगाना पड़ता है वह न मंगाना पड़े और हमारे देश में ही ज्यादा से ज्यादा तांबा हो।

इसी तरह बस्तर में कई जगह टिन मिला है। इस में भी आवश्यकता इस बात की है अधिक अधिक टीन हम अपने देश में उत्पादन करें। इस के लिए टेकनिकल नोवहाउ जितना और जैसा भी भी हमारे देश में हो उस को जल्दे से जल्द बढ़ावा दे कर टिन का उत्पादन हम करें।

तीसरी चीज यह कहनी है कि स्टील हो या कुछ और हो जो भी बड़े बड़े कारखाने हमारे हैं, एच० ए० एल० इत्यादि के उन सब में डिजाइन की बहुत बड़ी कमी होती है। जहां भी हमारी मेजर फ़ैक्ट्रीज हैं वहां डिजाइन के के लिए हम बाहर के देशों पर निर्भर रहते हैं। मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि डिजाइन भी हम अपने देश में तयार करें। जब तक डिजाइन अपने देश में हम नहीं बना सकेंगे तब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इतना ही कह कर मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRI S. N. SINGH DEO (Bankura): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to you for the opportunity you have kindly given me to speak on the Demands for Grants relating to the Ministry of Steel and Mines. Since the time at my disposal is very short, I would concentrate only on a few points and will be as brief as possible.

It is needless for me to say that the Steel and Mines Ministry has to play a vital role in building up of our national economy and the development of our country is, to a great extent, dependent on the development of this industry. We are glad that under the able leadership of Shri Chandrajit Yadav, the steel industry has not only made a rapid progress towards self-sufficiency but has also made a sizeable export, thereby earning valuable foreign exchange for our country. We are equally thankful to him that he has introduced workers, participation in the management of steel plants. This has not only led to a sense of enthusiasm but also to a sense of awareness among all sections of the workers As such, we welcome such a move. But simply their attendance at various levels and in different committees is not sufficient. There is a need for giving them the basic knowledge of the issues involved at the level of management so that their contributions could be more effective. Further, technological and management education should also be imparted to them so that they might play an effective role in increasing production.

We have seen, a few years ago, we used to import steel to the extent of Rs. 250 crores. But now the things have changed altogether. We are now going to export steel worth an

equal amount to various countries in the world. This is no doubt very encouraging. The Ministry as well as the workers of the steel plants are all to be congratulated. If we look to the export earnings of the steel industry, we find that from a mere Rs. 19 crores in 1972-73, it has gone up to Rs. 110 crores in 1974-75 and is expected to go up to Rs. 250 crores by the end of the current year.

We are very fortunate that so far as the mineral resources are concerned, we are very rich in them, particularly in high grade iron ore, coal, manganese, limestone and dolomite which form the most important ingredients for steel. Enough raw material is available in the country and the labour is also very cheap. There cannot be any reason why we cannot produce steel at a cheaper rate and compete successfully in the international market and make substantial profit out of it.

I would now like to speak about IISCO at Burnpur which was lying in a very bad shape the management of which the Government was forced to take over in 1972. Its working has now improved a lot. The production of saleable steel has gone up by 44 per cent during the current year. A programme of rehabilitation of the plant costing Rs. 55 crores has been taken up but up till now only Rs. 34 crores have been spent. If the remaining amount is given at an early date, I am sure, the production of the plant will reach its rated capacity. The General Manager of the Plant, Mr. Chatterjee, is doing very good work in this direction.

Moreover, they have already started the production of automobile rims and low alloy high tensile steel which have a ready foreign market. I would rather suggest that instead of going in for the usual conventional items in our steel plants, if we go in for such items as, have got good foreign market, then that will be in our own national interest.

I would also like to draw the attention of the hon. Minister to the question of appointment of Class III and Class IV staff in IISCO. It is quite strange that, at present, only candidates from the Asansol Employment Exchange are being recruited for employment in IISCO whereas from other employment exchanges no preference is being given, as a result there is a great discontentment among the people of that area. I would request the Minister to kindly look into the matter and give necessary directions to this Company so that candidates from other Employment Exchanges, if they are qualified, can be taken into service.

With these words, I support the Demands

14.00 hrs.

श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान बोकारो स्टील कारखाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अब तक बोकारो, दुर्गापुर, रूरकेला तथा अन्य जो भी बड़े बड़े कारखाने भारत सरकार की ओर से बनाये गये हैं, उन के सम्बन्ध में मुझे जानकारी मिली है कि क्लास 3 और क्लास 4 में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उन में हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों का नौकरियों में जितना अनुपात होना चाहिए, उतना अनुपात उन्हें नहीं दिया गया है।

मुझे स्वयं बोकारो जाने का मौका मिला। मैंने वहां देखा कि जिन लोगों की जमीनें फैक्ट्री बनाने के लिए ली गई थी उन लोगों के रहने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि बोकारों फैक्टरी बनाने के लिए जिन लोगों के घर तोड़ कर उजाड़ दिये थे, उन के लिए जितनी जल्दी हो सके मकान बनाने की व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिये।

श्रीमन्, बोकारो में प्रतिदिन 1 हजार से 1500 तक लोग एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज

[श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव]

में नौकरी के लिए अपना नाम अंकित कराते हैं, जिन में अधिकांश बिहारी लड़के होते हैं, खास कर उत्तर बिहार के लड़के होते हैं और वे महीनों तक नौकरी की इन्तजार में वहां पड़े रहते हैं, लेकिन उन को नौकरी नहीं मिलती। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है—निकट भविष्य में आप जब भी बोकारो जाय तो वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर से सूची लेकर देखें कि कितने स्थानीय लोगों को, बिहार के लोगों को नौकरी में लिया गया है। मेरा आप से अनुरोध है कि आप उन को वहां पर नौकरी दिलवाने की समुचित व्यवस्था करें जिस से उन शिक्षित युवकों को जो आज नौकरी के लिये वहां दर-दर मारे-मारे फिर रहे हैं, नौकरी मिल सकें और उन की रोजी रोटी का प्रश्न हल हो सके।

इसी तरह की स्थिति दुर्गापुर में है। वहां भी जो हमारे गरीब हरिजन, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के युवक हैं, वे नौकरी के लिए एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज में अपने नाम रजिस्टर कराते हैं और बरसों तक दुर्गापुर में नौकरी के लिये दर-दर घूमते रहते हैं। वहां भी जिस अनुपात से उन को नौकरी मिलनी चाहिये, अभी तक नहीं मिल सकी है। इस लिये मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि निकट भविष्य में आप जब भी दुर्गापुर जांय—जिस अनुपात में आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिये, उस की समुचित व्यवस्था जल्द से जल्द कराने की कृपा करें।

जहां तक लोहे की कीमत का प्रश्न हैं मेरा कहना है कि जैसे गत वर्ष 60, 70 रु० मन धान बिकता था और 105 रु० चावल बिकता था उसी अनुपात में लोहे की कीमत भी कम होनी चाहिये। गत वर्ष जिस कीमत पर लोहे की छड़, मकान बनाने के लिये बीम या और आवश्यक लोहे की चीजें बिकती थीं तो जिस अनुपात में देश में अन्न की कीमत कम हुई है उसी अनुपात में लोहे की भी कीमत कम होनी चाहिये जिस से किसान अपना छोटा मोटा मकान बनाने के लिये आसानी से लोहा खरीद सकें। लोहे की कीमत में कमी के लिये जितनी जल्दी हो सके आप उस की व्यवस्था करें।

अन्त में मैं आप के माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने इस मंत्रालय के काम को सम्भाला और बहुत तेजी से काम बढ़ाया उस के लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI CHANDRAJIT YADAV): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to all the hon. Members who have participated in the debate on the Demands for Grants of my Ministry. Almost all of them have appreciated and commended the work done by this Ministry during the last one year and have expressed their satisfaction They have also given many valuable suggestions, so that we can take advantage of those suggestions and improve our work further.

I would like to tell all those hon. Members who have had a word of appreciation for the work done by my Ministry, by the workers, the engineers, the technicians and managers in all the undertakings under my Ministry, that I would convey their feelings to them, and I am sure that these appreciations will encourage them and give them further strength to come out with better performance, to show greater ability and work with greater determination and dedication during the current year.

I would not like to go into many facts, but it will be proper for me if I put a clear picture, the total picture of the Ministry of Steel and Mines before this House, so that the country may have a better understanding and may also understand the important role the Ministry has to play in future.

I was just looking into the speech of my predecessor, the late Mohan Kumaramangalam, in whose regime many important steps were initiated. When he was speaking in this House on May 4, 1972—there was criticism that the steel plants were not working to full capacity, at that time the production from the steel plants was 65 to 67 per cent of the installed capacity—he expressed this hope:

> "If we are able to bring up our production from the present 65 to 67 per cent level, which it is today, to the level of 80 to 82 per cent which we aim at, I have no doubt that we shall be able to bring down our steel prices to possibly among the cheapest steel in the world."

This was his objective and in those circumstances perhaps he felt that it would be a great day for Indian steel industry if we would be able to produce 80-81 per cent of our utilization capacity. Today, because of the extreme good work and cooperation given by our workers in the steel plants, because of the imagination and better coordination of our managers in the steel undertakings, because of a greater sense of discipline and awakening and a proper guidance to our managers and workers, in the outgoing year we have been able to produce 84 per cent of our utilization capacity. In the current year, we are planning to increase this utilization capacity. and I would like to assure the House that our efforts are that we must reach, and we can reach in India, the world level of utilization capacity of the steel industry. We will not be satisfied unless and until Indian steel mills produce on an average at least 90 per cent of the utilization capacity.

When I am saying these things, I am not saying just out of idealism, or any ambitious programme, but on the basis of certain facts. Only during the last month, that is April, Bhilai workers were able to produce 112. per cent of their utilization capacity. This is something very encouraging; this is something which our workers, really speaking, have placed as a kind of ideal before the working class and the other industries of this country.

I am sorry that Shri Mohammad Ismail made certain unfounded allegations that trade unions have no place in the steel industry and the trade union interests are not being looked after properly. I would like to tell the House that this is one industry where we have got a National Consultative Committee of Trade Unions, where all the trade unions are represented on that body. There, after every three months, the management and the trade union leaders sit together. They discuss not only about the day-to-day problems of the workers, but they also discuss the problems of the industry as such. They discuss production plan, they discuss target for the future, they discuss the welfare activities of the workers, they discuss how to increase production of steel plants and I have asked the Consultative Committee of the Steel Industry that they should even discuss the long-term planning and they should give their valuable suggestions, how we can reduce the cost of production, how this highly investment-intensive industry can be made more profitable, and how cost can be reduced seeing the circumstances in our country. I must say that many useful suggestions have come from that body. We discuss even the target with the trade union leaders. The discussion on the annual target starts from the shop floor level, then it is discussed at the plant level, National Consultative Committee level and then finally the SAIL and the Ministry decide the target. For the year 1975-76 a target was fixed for all integrated steel plants. I am glad to say that that target has been exceeded by producing 78,000 tonnes i.e. 1.4 per cent more steel than what was originally fixed by the Management and the workers. We produced 8,78,000 tonnes more i e. 18 per cent more than in the Corresponding year 1974-75. I am talking in terms of saleable steel. Now we have decided that the capacity utilisation and the production will

[Shri Chandrajit Yadav]

be calculated on the basis of saleable steel.

We have also planned for 1976-77 on the basis of our experience, on the basis of the steps which have been taken during the last year, and that Indian stel plants will be able to produce 8.205 million tonnes of ingot steel in 1976-77, which corresponds to 6.465 million tonnes of saleable steel. This in terms of perentage will be 13.2 per cent and 11.8 per cent respectively higher than the production in 1975-76 We have also emphasised that in 1976-77 reduction in costs and operating expenses should also take place.

A few years ago the country used to face a serious situation There was a scarcity of steel, the prices were ruling very high and because of high prices and scaricity of certain steel items, certain anti-social elements such as hoarders, blackmarketeers, and speculators, were taking full advantage of the situation and they were exploiting the general consumers, because, at that time, we were not able to produce steel according to the needs of our consumers. But, I am glad to say that toady the blackmarketing and the hoardings are things of the past. In steel, we have seen to it that as the general atmosphere has been created in the country. steps have been initiated by the Government against all anti-social elements and we have seen that hoarding and blackmarketing should not be allowed.

Today, really, we are facing a different problem It is a problem of surplus of steel. Our demands are not as high as they should have been. I agree with the criticism of those Members, that in a country like India the rate of growth should have been much higher The consumption of steel should have been also much higher. But, after all, we are a country where so many factors prevail. I am not going to speak on the general economic situation of our country. Views have been expressed and steps are being taken, it is not that the Government is not seized of this serious situation, it is because of that, that under the leadership of our Prime Minister, certain bold steps have been taken not only on the political front but also on the socio-economic front and 20-Point economic programme is one significant and important step towards a self-reliant economy in our country, towards a higher rate of growth and also towards removing poverty and removing socio-economic disparity amongst the various sections of our society.

When there was surplus of steel we had to take certain steps. The first thing which we did was this. The distribution system was completely reoriented. We saw to it that all red-tapism was removed and consumers got steel without difficulty. We saw to it that steel was made available to them easily The number of stock-yard was increased. We also sought the cooperation of private traders that they should also cooperate and they should act within rules and regulations and at proper profit rate they should be able to supply steel to ocnsumers. Since the availability became better, certain controls on end use of steel were removed. It is not that Government has made any drastic change. Due to some misunderstanding or wrong assessment certain criticisms were made that Government has removed controls on steel and it has brought some significant change in policy. It is not so. Nobody can come to this wrong conclusion. After all, controls are for the benefit of the people Controls are to see that anti-social and undesirable elements are not allowed to take advantage of scarcrity situation. Because the availability was better, in the interest of the consumers, in the inttrest of small industrialists, certain relaxations were made. I am glad to announce that this has brought good results. This has helped the small industrialists and people at large. At that time when home demand was not high and production had picked up very well a

suggestion was made that we should cut back our production. We did not agree to that suggestion. After a long time the steel plants started working much better. Their utilisation capacity was much higher. The morale of workers and management was very high. Therefore, we thought it would be wrong on our part to cut back the production. Many other countries like Japan, West Germany UK, etc. cut back production. But we did not do it.

Since there were these special circumstances we thought that we should explore the possibilities of exporting our steel. During last year SAIL International was able to register export of about more than 2 million tonnes of steel. The actual figure was 21,83,325 tonnes valued at Rs. 308.17 crores. Last year we were able to ship steel amounting to Rs. 113.52 crores and in terms of quantity it was 8,10,544 tonnes. A criticism was made that we are exporting steel at subsidised rate. This is not correct. Though in the international market we have to purchase and sell steel at prevailing international prices, I am glad to say, in regard to these various categories of steel which we have been exporting, they have accepted our steel at a reasonable rate of profit.

The home price in certain items, for example, like rails, was round about Rs. 1200 per ton and we were able to sell our steel from Rs. 2000 to 3500/- per ton. And, as it has been rightly pointed by some hon. Members, India, for the first time, was able to compete with the giant steel producing countries and, in many global tenders, on the basis of price and on the basis of quality of steel, we were able to win tenders and we sold our steel at a reasonable rate of profit. This happened for the first time in our country.

Therefore, Sir, I would like to remove this impression that we are exporting steel at a loss. We have not even approached the Finance Ministry for any subsidy for export. Many industries in this country have got export subsidies but the Steel Industry did not approach the Finance Ministry for export subsidy.

Of course, in one or two items, we had to export our steel at lower prices. That was because of the prevailing international price then. Therefore, we had to sell our steel at that price. Some other important steps have been taken during the last on year. The most important of them is this Some Members here expressed their views. But, I would like to tell you that India, fortunately, is a country, which has got many important inputs; we have got rich iron-ores; we have got mill; we have got man-power. Now, we have luckly got a good organisation. We have, for example, the designs organisation and engineering organisation in our country. An organisation like the MECON can be compared with any well developed organisation of the world. To-day, MECON has about 2,500 people on its staff including about 1200 engineers, designers, technicians and it has made a valuable contribution in building the Bokaro Mill. When this country started Bhilai, we had to import almost 90 per cent of the equipment in the first stage and also the know-how But, from Bhilai., we now have reached the stage of Bokaro where only on 1st May this year, May Day, among many of the working class people of this country and from all over the world, our Prime Minister was kind enough to go and inaugurate the commissioning of the hot strip mill of Bokaro. When we complete Bokaro, it will be a matter of great satisfaction for me and for the country as such what we can say that in Boakaro, the situation has been completely changed. By the time we complete second stage of Boakro, Indian equipment, Indian machinery, Indian designs and Indian knowhow will make 86 per cent of their contribution in this biggest steel plant of our country.

[Shri Chandrajit Yadav]

We therefore feel that in the current year our effort will be that we would see that the Indian Steel Industry should prepare itself to take a big march. I personally feel, and I feel with a great conviction, on the basis of the realities, on the basis of the situation prevailing in this country, with its vast resources of iron-ore, coal and, as I said, man-power—skilled man-power—and with a new sense of determination and dedication which has been generated in this country today and with a much stronger, and agricultural, base of this country, we can and we must plan for the next twentyfive years for steel production. That is why Government has asked the SAIL to take up longterm planning. My ministry has appointed two important steel consultants in this country—MECON in the public sector and Dastur & Co. in the private sector because, in these areas, there should be no discrimination between public sector and the private sector so far as technology is concerned, so far as engineering is concerned and so far as designing is concerned.

So, we have appointed both of them as consultants. Directions have also been given that the SAIL should appoint a Committee including these two Consultants and they should see that this country has a blueprint, as a proper longterm planning, as to how much of steel we can produce by the end of the century and what would be the requirements of this country and what will be the product-mix required by the people of this country. Of course, these will not be done in an isolated manner. We have to look and we have to see the general economic situation of our country

We have to see the rate of growth in our country and, therefore, we feel this important work has to be done I am one of those who feel that India will be in a position by the turn of the century to produce at least 70 million tonnes of steel in this country. When I say this, I say so with confidence because I visualise that by the end of the century our own requirements will be 50 million tonnes. Can we afford to import steel in spite of our having all the inputs available in our country? When I made this statement a few months ago there were many people the so-called steel magnetes, who were very critical. They said that the Minister is ambitious as he is planning 75 million tonnes of steel by the end of the century which we cannot do on the basis of our resources.

Sir, I am reminded of a criticism which was constantly levelled against our great leader, Pandit Jawaharlal Nehru, when he had decided to set-up three steel plants in the public sector and each of them with one million capacity. Then he was dubbed as a mere visionary and an unpractical person but his vision was not blurred by such criticism because he could visualise the development in this country as well as all over the world 25 years ahead. Sir, today it is because of his great vision and understanding that we are in a position to say that India is self-sufficient so far as steel is concerned and I would like to assure the House that India would continue to be self-sufficient so far as steel industry is concerned.

Sir, certain suggestions have been made that we should develop our technology and also see to it that our research and development takes place in proper perspective. We have a well-equipped research and development organisation but I feel that there is need to strengthen that organisation and also see to it that the latest technology available all over the world is also utilised in our country. We should be able to reduce the cost of production and also the cost of investment Steel industry has become a highly investment-intensive industry. Certain hon. Members have expressed their concern that our cost of investment per ton is very high. I have got

the figures of some important countries and I would like to say that India's cost of investment at Bokaro is Rs. 5,000 per ton and we feel that in the new plants which will come up in future the cost of investment per ton will be Rs. 4.100. In U.S.A. the cost of investment per ton is Rs. 5,000 in some plants. In Japan where the cost of investment per ton is the lowest it is Rs. 2.250. In South Africa the cost of investment per ton is Rs. 4,950 whereas in Guyana it is Rs. 6,078. In Brazil the cost of investment per ton is Rs. 8,974.

But, Sir, there is a method of calculating the investment cost per ton also.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): How is it that when Bokaro's investment is Rs. 5000 per tonne, in future plants the investment will be only Rs. 4100 per tonne?

SHRI CHANDRAJIT YADAV: Because in certain countries, really speaking, a certain number of shops like refractory, materials plant, plant, repair and maintenance shops, ingot mould foundry etc. are not included when the cost of investment is taken into account. In certain countries, even oxygen plants are not put up because oxygen can be bought from regular suppliers who establish oxygen plants in the vicinity of the steel plants Power plant capacities are substantially lower in steel plants in developed countries in view of the stability of the power system and the availability of bulk power from the power grids All this results in higher investment for the steel plant proper installed in India now. I may tell our elder friend, Tiwaryji, that by that time perhaps India's public sector steel plants will have some refractory plants, some oxygen plants and our power capacity also will be much higher and we hope that the cost of these items which are now included in investment will not be there and hence the cost of production will be lower.

Therefore, we are fully aware of these factors. Steps have been taken and directions issued that our design and engineering irganisation and the research and development organisation should take necessary steps so that they may be fully in tune the developing technology all over the world and in our own situation they should see how the cost of production can also be reduced in our country. Steel technology the world over is developing at a very fast rate and I would like to assure you that we are very conscious of it that we cannot afford to be left behind in this global race: nor can we content ourselves with being a buyer of foreign technology in these vital sectors. We will have to be self-reliant and, therefore, necessary steps are being taken, Our scientists, metalurgists and technical men will pool their resources so that we are able to enter the new era in steel making processes on the basis of our own knowledge and technology. For example, the encouraging results we are getting from our exploration in the Bombay High make us reasonably hopeful of striking gas there. Sponge iron technology is almost entirely dependent on the gaseous process and even the pelletisation process will also be facilitated if we can get natural gas in our country Unfortunately, at present we do not have enough natural gas but there are signs and indications and we hope that if we get gas at Bombay High, it will go a long way to help this industry

Criticism has been made that we are exporting iron ore and it is asked, why should we not export steel. On the one hand, the criticism now is that we are exporting steel, we should not, we should see the profit content of it. On the other hand, we should also not export iron ore. It is difficult for me to agree with this proposition. We would like, instead of exporting iron ore, to export pellets Very recently we had a very impor-

[Shri Chandrajit Yadav]

tant agreement with Iran. One of the biggest mining projects, Kudremukh, is being established in our country; it is not only one of the biggest in our country, it will be one of the biggest in the world. Instead of exporting iron ore, we are going to export iron ore slurry. We are negotiating with some other countries on the question of Donimalai, Bababudan and the finds available in Baildailla so that we should be able to export pellets instead of iron ore. Certain steps have also been taken.

Shri Halder made this criticism that perhaps we have deviated from the public sector concept in the steel industry. He says that we have handed over the very important steel industry to Chowgules It is a very wrong understanding of the whole thing. I want to tell him very frankly that there is a very basic policy; the Government of India have decided long back that the basic industries will remain in the public sector and in future they will also expand in the public sector. There is no question of deviation Pellet plant should not be compared with the steel industry and the steel mills. The pellet plant which is going to be set up in Goa was individually negotiated by Mr. Chowgule in respect of the financial aspects, know-how and technological arrangements, etc. The Government of India insisted that in this plant SAIL will have 33 3 per cent share and Chowgule will also not be allowed to own more than 33.3 per cent and the rest 33.3 per cent will go to the public and therefore in the management and control the government and the people of this country will have an effective say.

We are fully aware of the developing technology and we know that because of air pollution and the rising freight, people would like to purchase pellets instead of iron ore and therefore we are getting ready for the future to set up pelletisation plants in our country and so long as we do not reach that stage, we should not stop the export of iron ore; it will not be in the interest of our country. Fortunately we have got enough iron ore in our country. According to present estimates India has got proven iron ore reserves of more 10,000 million tonnes; and still almost every year we get the good news of more iron ore mines Surveys are being made and exploration activities are being undertaken and we feel that even if India reaches a very high rate of a steel production, one of the highest in the world, even then we will have enough iron ore for a very long time. But I agree with hon. Member Shri Damodar Pandey that we should see to it that this very important mineral resources of our country, this very important national wealth should not be allowed to be wasted by private people; they should not be allowed to play havoc with the iron ore deposits by exporting the best quality ores and wasting the low quality ores. That is why the Iron Ore Board has gone into that aspect and they have submitted a report to the government and that report is under consideration of the government. We are likely to take certain steps so that the important mineral resources of our country are not slaughtered by private individuals or private mine owners causing much harm to the interest of the country.

We have great satisfaction that during the last year industrial relations were ideal in all the steel plants. There was no manpower loss. After a long time workers' committees have been functioning very effectively and satisfactorily. Certain allegations were made that the trade union workers were not taken into confidence I should like to say this The Durgapur steel plant had reached a stage where it was stagnating; it was producing less than 30 per cent of its capacity due to continuous strike and industrial trouble. It was supposed to be the sick child of the Indian steel industry. I am happy to say this; the

CITU is in power; it is the recognised union; but because of the all round co-operation from everyone including CITU, INTUC and AITUC, last month the Durgapur steel plant production was 82 per cent of its capacity, slightly more than that. When I myself visited that plant, on the spot, all the three unions came together in deputation, INTUC, AITUC and CITU, and they gave me in writing their satisfaction at the way the workers' participation scheme has been implemented in that plant.

And they gave me the assurance of their full co-operation. Therefore it is not good to generalise this issue and put it in a way which is completely against the facts. Mr. Ismail may say here many things. But his own trade union workers had given their assurances of full co-operation and they had expressed great satisfaction. We do not want to act with a sense of vindictiveness. Vindictiveness does not help anyone, and it will not help. During the Emergency, I must say that the working class all over the country, as the other brethern and sisters in other walks of life, have realised that India has entered into a new era in which disruption and indiscipline will not pay and it will hurt their interests as well as the national interest also. Therefore, a new awakening, a new realisation has come and we want to take full advantage of this new awakening. We want to co-operate with the workers. We want them fully to get involved in every process of the industry and therefore I am glad to say that many hon. Members have very rightly paid compliments. In the steel industry, all the undertakings under the Steel Ministry—almost all of them except one or two where we are also taking steps—we have seen that the workers' participation has taken place and the scheme is not only working successfully but the meetings are taking place. The workers are working with greater confidence and coming forward with much greater co-ordination. On this occasion, I would like to say that at this stage, we have taken only a step to form the workers participation committee at shop floor level, but we will not be satisfied with this. This is the first step, a very important step, and I will see to it that the workers' participation which has been initiated and which has been initiated at shop-floor level goes to the highest body, to the Board of management level where workers' representatives will have a full say and they will make their valuable contribution.

(Interruptions)

Sir, many incentives have also been given to our workers. I have a great satisfaction that last time when we had entered into a Wage Agreement for the next four years, it was with the full consent of the trade union. We sat for four days continuously in Delhi and we saw to it that with the full consent and full agreement of workers, we were able to reach an agreement and we had seen that that agreement had been fully implemented Last time, when I visited almost all the steel plants, I did not go to see the machines of the steel plants. I had seen them earlier. But I wanted to see the facilities provided there. I saw their hospitals, I saw their schools and I saw to it that indebtedness was removed from the workers in these steel plants I saw to it that the workers' participation scheme is properly implemented and I am glad to say that this aspect has been taken care of in almost all the undertakings and it is matter of great satisfaction for us

I would also say that so far as the Mines Department is concerend, my colleague, Shri Sukhdev Prasad, has made certain points and has mentioned about the progress in this field The outgoing year has been a turning point in the exploration and development of non-ferrous metals There was an increase of 30 per cent over the earlier estimated plan outlay during the year. At the beginning of the year, the estimate for the plan outlay

[Shri Chandrajit Yadav]

was Rs. 91.0 crores reflecting the accelerated progress and development works. The actual expenditure during the year was Rs. 118.0 crores. The production of aluminium during 1975-76 has been higher and it is an all time record. It is 48 per cent over the production of 1974-75. As it was mentioned here, we were planning to import aluminium in this country and our valuable foreign exchange would have been spent. But at that time we said with confidence that now we were in a position that we would not only stop the import of aluminium but probably export also. Today I am able to say that we are keeping up our word. This year India has exported more than twenty thousand tonnes of aluminium.

Probably by the end of the year, we would be able to export much more because our production is picking up. BALCO is the only public sector undertaking in the country which has been commissioned to produce aluminium. In the very first year of its production, its production is at a very satisfactory level and its quality is good. It has been able to export EC grade aluminium to a country like Japan, which has been very much appreciated. We would be able to commission the other units in BALCO subject to availability of power. Otherwise, the plant is ready

Coming to copper, production of blister copper during 1975-76 increased by 51 per cent over that of 1974-75 and of copper wire bars by about 50 per cent. The production of zinc has been higher during 1975-76, an all time record. The increase in production during 1975-76 over 1974-75 is 26 per cent. The target of zinc production for the year 1976-77 is 43,000 tonnes which is about 72 per cent over the production for 1975-76. Production of primary lead was also higher during 1975-76.

We are fully conscious of the fact that production of non-ferrous metals is very important for the industrial development of the country. We were not self-sufficient in it, but we are trying our best. Fortunately India today is placed in a very fortunate situation. As in the case of iron ore, we have discovered a very a vast reserve of high grade bauxite. Mention has been made about Orissa and Andhra areas having bauxite Everything possible is being done. Only about six months back, MEC has been given a special grant of Rs. 30 lakhs to intensify their mapping and exploration activities so that we can take advantage of this important mineral. Today many countries are keenly interested in having some kind of collaboration in setting up an alumina plant in our country We will take about 18 months to reach a final conclusion about how much bauxite is available in our country. Taking into account our internal need, if necessary, we will see that in the interests of the country proper investment is made. If collaboration on reasonable terms is available, we would also enter into that

Reference have been made to small minerals like manganese, chromite, etc Though they are small, they are very important and the government is looking into the question whether private miners will be allowed to do the mining, whether there should be a better organisation to do it, what should be the policy, etc Whatever decision is taken, it will be in the interests of the country and necessary steps will be taken.

About copper, the question of Malanjkhand has been raised. Because we are deficient in copper, Malanjkhand find is very important. The content of copper is much higher The reserve also is good. Therefore, the government has made a provision of Rs. 3 crores for it, which is the amount needed for it. Enough money will be made available, so that the

Malanjkhand mine is developed according to schedule and necessary steps will be taken. Therefore, there should be no misgiving in the minds of the hon. members on this score.

There were certain points made by many Members. It will be difficult for me to go into the individual questions. I have tried to cover the general points which have been made by Members. But it is necessary that I should dispel the doubts from the minds of the Members about certain things. I do not know whether I was able to dispel doubt from the mind of hon. Shri Halder because his whole speech was motivated and partisan.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): That was for the good of the country. I expressed my view from the national point of view.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: We know much better what is the good of the country There should not be any misunderstanding in your mind that only you know the good of the country and not we.

I would like to say that it is completely wrong to say that the Government has given up the policy of expanding the steel industry in the public sector and is handing it over to the benefit of the private sector or vested interests, as he has charged It is a completely baseless charge and it should not go home.

On the question of the trade union's role, I have gone into that at length. Therefore, I do not want to take the valuable time of the House on that question.

About certain allegations that some workers have been victimised, it is a fact that certain actions have been taken against a few dozen workers. He has mentioned the figures—6 at Durgapur, 8 to 12 at Rourkela, one at Bhilai—and it is a fact. We would do our best to look after the Welfare of the workers. We have taken certain important steps to see that workers work to their full satisfaction. Steel Plants will not run on the basis of only better management, better maintenance of the machinery and better know-how. If they have to run satisfactorily, the most important thing is the human factor. The workers must feel satisfied and the workers must feel that it is an industry which is run with their cooperation, in their interest and in the country's interest. That is what our efforts are. We want to create that climate not only in the steel industry but also all over the country. I would say very frankly that if motivated, anti-social and disruptive elements want to do their politics, want to disrupt the production of steel plants and also want to damage the valuable machinery of steel plants and if they go on doing that, then in the interest of steel industry and necessary discipline, action will be taken and will have to be taken. But we have been very careful. in taking such action I have told the General Managers that Emergency should not be used like bull-dozers. Emergency has given us an opportunity where a new sense of discipline, new kind of determination and new atmosphere have been created in the country. We have to make use of that and we should see that that characteristic should become part of our habits and our national character. We do not want to take the help of the Police; we do not want to take advantage of the rules and regulations in the factory. Several times, these hon. Members met me and I have explained the position to them. I would again like to assure them that individual cases will be looked into and if any injustice has been done to any worker, that will be rectified. I will say that no worker will be victimised because of any attitude of vindictiveness or because of any wrong understanding on the part of the management.

SHRI MOHAMMAD ISMAIL: He has not replied about JK Aluminium.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: In spite of our best efforts, the JK Aluminium factory could not start. I am fully aware of the agony of the workers who have been rendered idle,

[Shri Chandrajit Yadav]

unemployed for almost a year, perhaps more than that.

15.00 hrs.

Sir, we have looked in that question. We took a decision. Certain concessions were given, so that that plant was given some help which it needed, so that they should be able to start. Really speaking, they went in for a loan; and the loan was not granted to them; and that is why there is delay. I have talked to the Finance Minister; I have talked to the Minister of Industry and on the 22nd May their application for loan is coming up again for reconsideration and we have agreed that the loan will be provided. And we will see to it that the factory opens and that the maximum number of workers who have been rendered idle, go back to their work. Suitable steps will be taken. *(Interruptions)*. So far as the expansion question is concerned, as I had said, this study is being made. I know that to-day if we have to go in for a greater production of steel, the first problem, in my opinion, will be the expansion of the existing plants where the possibilities are there. That will be cheaper as also in the interests of the country. The second point is that we have already commissioned three important DPRs for the southern plants. So far as Salem is concerned, I would like to inform Mr. Alagesan that we are fully seized of the situation. It is being considered at the highest level. We are facing certain difficulties, but money will be made available and at least the work will start; and necessary money will be made available for the Salem steel plant. So far as the other plants are concerned, as soon as we get the survey reports and the financial position allows us to invest, necessary steps will be taken. Some feasibility reports have also been made in regard to those areas where iron ore is available in abundance.

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar): What about your promise regarding expansion of Rourkela?

SHRI CHANDRAJIT YADAV: Perhaps the hon. Member did not listen to me when I said that when the expansion programme takes place, the existing plants will get first priority. *(Interruption)*. In regard to Rourkela, already certain important expansion programmes are going on; CRGO and other special steels are really going to be produced at Rourkela and a kind of expansion is in progress there. So far as mild steel is concerned, it will depend upon the availability of resources. We are ourselves keen that our steel industry should develop as fast as possible; but certainly it depends on many factors.

I would be failing in my duty if I do not refer to the Chasnala tragedy, though this House has discussed it in detail. It was a very major tragedy. Our hearts go out to the families of the victims. We are trying to help those families to the maximum possible extent; and many important steps were taken so far as the Chasnala relief work was concerned. Ex-gratia grants were made to each family. I am not going to repeat it. The compensation, according to the old rules, was only Rs. 10,000. Now we have amended the rules. Instead of Rs. 10,000, every workers's family will get at least Rs. 21,000. Besides that, we have also seen to it that we provide one employment to every such family. IISCO offered employment to 346 dependents. 283, including 110 widows, had availed of this offer. 49 offers were made by other organisations.

Till 1975-76, a sum of Rs. 38 lakhs has been received in the Chasnala Emergency Fund. This amount is being utilized as follows. Where no widow member of the affected family can avail of the employment offer, an amount of Rs. 10,000 should be provided for the family and put in fixed deposit. First we are offering employment. But, because of old age or because there are children, if they are not able to take advantage of this

offer, then we will give Rs. 10,000 to each family. Then we provide Rs. 5,000 per family for construction and repair of their residential accommodation.

Of the three officers' families, two were entitled to get Rs. 1 lakh each from the Group Insurance Scheme of LIC. The third officer was not confirmed and so his family was not entitled to such compensation. Therefore, from this fund we have provided Rs. 30,000 to be paid to this particular family.

Each such family will be granted Rs. 10,000 for education of children, to be put in long-term fixed deposit. The Government of Bihar is providing 0.04 acres per family in Bihar for the construction of a house and a further *ex gratia* amount of Rs. 1,000 for each family. They would also provide employment in the State Government Departments and Undertakings to the dependents who are 18 years of age, and provide educational facilities to the dependents.

Under the Coal Mines Fatal and Serious Accidents Benefit Scheme, an allowance of Rs. 75 per month is to be paid to the widow for a period of five years. If the allowance is to be paid to a dependent other than a widow, then it is Rs. 50. Then, Rs. 15 per month will be paid for five years for each child of school-going age, and its revision is under consideration.

It is proposed to extend the free medical treatment in the hospitals of coal mines welfare organisations to wives, wholly dependents, unmarried children up to 21 years and dependent parents.

To encourage re-marriage of widows, it is proposed to remove the condition that the widows will become ineligible for family pension and monthly allowance if they marry.

A Special Cell has been set up in the Coal mines Welfare Association to look into these measures. Lady welfare inspectors have been posted to attend to the problems of women particular.

A major part of the relief and rehabilitation has been completed. Members of the affected families have recovered from the initial shocks. Now we are trying to see that these families are helped as much as possible.

Here I would like to express my gratitude to the various organisations and individuals all over the world who came forward to help the affected people and gave money very generously to the Committee which was formed under my chairmanship for the relief work of these families. We were able to get Rs. 38 lakhs for this fund. The hon. Member, Shri Damodar Pandey himself came and presented a cheque for Rs. 3.8 lakhs to this fund. We hope that the other organisations which promised us help will also come forward with their help and that the entire money will be used for the benefit of the affected families in various ways.

With these words, I would again like to say that I am grateful for the very friendly words which have been spoken here, which will go a long way to give encouragement not only to the officers in my Ministry but also to the workers and officers who are working at the plant level, because of whose really good work and contribution we have been able to make this progress. We are fully conscious of the important role this Ministry and the steel industry has to play in the reconstruction and development of our country in its march towards progress. I would like to assure the hon. Members that whatever suggestions they have given here will not go unnoticed. We will look into them and see that steps are taken for the implementation of those suggestions.

With these words, I request that the House may pass the Demands.

SHRI D. K. PANDA: Only one question.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has given a very elaborate reply. I think he has coverd a very wide field and he has taken more than one hour. I think we should end there.

SHRI D. K. PANDA: I referred to the reported espionage activities going on in Tisco. We had raised so many other questions like that.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: I think Mr. Panda will agree with me that the question of espionage activities said to be carried on by a foreign organisation in the Jamshedpur area is not my concern. It is for the Home Ministry to look into that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are no cut motions.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1977, in respect of the heads of demands entered in the second column hereof against Demands Nos. 83 to 85 relating to the Ministry of Steel and Mines."

The motion was adopted.

[*The Demands for Grants, 1976-77 in respect of the Ministry of Steel and Mines, which were voted by Lok Sabha, are shown below.*—]

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 23-3-1976		Amount of Demands for Grants voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue	Capital	Revenue	Capital
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
83.	Department of Steel	8,90,89,000	88,52,25,000	44,04,41,000	226,26,25,000
84	Department of Mines .	4,75,000	..	23,75,000	..
85	Mines and Minerals .	6,00,93,000	16,70,52,000	20,04,68,000	83,52,62,000

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

MR DEPUTY-SPEAKER. The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 69 and 70 relating to the Ministry of Law, Justice and Company Affairs. Hon. Members present in the House who desire to move their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

These two Demands, i.e., Demands (Nos. 69 and 70, will be discussed till 6 p.m. As Hon. Members are already aware, guillotine will take place at 6 p.m.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Will there be a reply by the Minister?

MR. DEPUTY SPEAKER: If you want the Minister to reply, some time can be found before 6 p.m.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Otherwise, what is the use?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day